RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

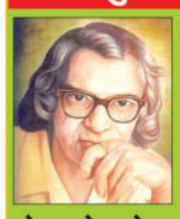

हमारा मन जिस प्रकार विचारों के सहारे आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मानव-चेतना प्रतीकों के सहारे विकसित होती है।

सुमित्रानंदन पंत

वर्ष-08, अंक - 18 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरूवार 05 फरवरी 2026 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

युमनाम खेमचंद बने मणिपुर के 13 वें मुख्यमंत्री, शांति बहाली सबसे बड़ी चुनौती

इंफाल।

मणिपुर को करीब एक वर्ष बाद पूर्णकालिक सरकार मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इंफाल स्थित लोकभवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में 356 दिनों से लागू राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया और एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का गठन हुआ।

मैतेई समुदाय से आने वाले युमनाम खेमचंद सिंह पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के करीबी माने जाते हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ रही है। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही उनके सामने राज्य में शांति बहाल करने और लंबे समय से चले आ रहे जातीय तनाव को कम करने की बड़ी चुनौती होगी।

नई सरकार के गठन में सामाजिक संतुलन साधने पर विशेष ध्यान दिया गया है। नगा समुदाय से आने वाले लोसी दिखो को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वे नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं कुकी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली नेमचा किपगेन ने भी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से दूरसंचार माध्यम के जरिए शपथ ग्रहण किया। नेमचा किपगेन मणिपुर की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनी हैं, जिसे राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से जारी जातीय हिंसा के कारण राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। इसी के चलते 9 फरवरी 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालात को देखते हुए 13 फरवरी 2025 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है।

राज्य के गृह मंत्री पद को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के अनुसार कोंथौजम गोविंदास सिंह का नाम इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए सामने आ रहा है, हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो 3 फरवरी को दिल्ली में मणिपुर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें युमनाम खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद 4 फरवरी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों की बैठक में मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के नामों पर अंतिम सहमति बनी।

बंगाल में ही क्यों, असम में क्यों नहीं हुआ एसआईआर - मुख्यमंत्री ममता

नई दिल्ली, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल में 2026 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय पहुंचीं। इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित रहीं। सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास से सर्वोच्च न्यायालय के लिए रवाना हुईं। न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान तथाकथित तार्किक विसंगति सूची में शामिल मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने के निर्देश निर्वाचन आयोग को दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न्यायालय में मौजूद रहीं। उन्होंने स्वयं बहस करने की अनुमति मांगी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने की सलाह दी और जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। पीठ ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को की जाएगी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर केवल पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के चलते अब तक सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई बूथ स्तर अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि विशेष सघन पुनरीक्षण केवल पश्चिम बंगाल में ही क्यों कराया जा रहा है, जबकि असम में इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और असम को खुली छूट दी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने के लिए निर्वाचन आयोग को एक दिन का समय दिया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करते हुए उसे ÷व्हाट्सऐप आयोग÷ बताया।

दो करोड़ की एमडी ड्रग बताई गई सामग्री निकली यूरिया, पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार

इंदौर।

मध्यप्रदेश की इंदौर पुलिस के लिए एक बहुचर्चित मादक पदार्थ जब्ती का मामला भारी किरकिरी का कारण बन गया। फरवरी 2025 में तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में जब्त की गई कथित दो करोड़ रुपये की एमडी ड्रग फोरेंसिक जांच में साधारण यूरिया (पोटेशियम नाइट्रेट) निकली। इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को विशेष अदालत ने स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

यह मामला 26 फरवरी 2025 का है, जब तेजाजी नगर पुलिस ने एबी रोड बायपास के पास कस्तूरबा ग्राम क्षेत्र में दो मोटरसाइकिल सवार युवकों को रोका था। आरोप है कि तलाशी के दौरान मंदसौर निवासी विजय पाटीदार और आजाद नगर निवासी मोहम्मद शाहनवाज के पास से 198 ग्राम सफेद पाउडर बरामद किया गया। पुलिस ने इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य की वाणिज्यिक श्रेणी की एमडी ड्रग बताया था। इसके बाद दोनों को नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। बाद में इस मामले में एक पुलिस आरक्षक लखन गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया था।

पुलिस ने जब्त सामग्री को भोपाल स्थित राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। जून 2025 में आई जांच रिपोर्ट ने पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि जब्त किया गया पदार्थ कोई मादक पदार्थ नहीं, बल्कि पोटेशियम नाइट्रेट है, जिसका उपयोग आमतौर पर कृषि उर्वरक और पटाखों के निर्माण में किया जाता है।

फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद तेजाजी नगर थाने के उपनिरीक्षक मनोज दुबे, प्रधान आरक्षक देवेंद्र परिहार, अभिनव शर्मा तथा आरक्षक गोविंदा और दीपेंद्र राणा को पुलिस लाइन में भेज दिया गया था। वहीं आजाद नगर थाने में पदस्थ न्यायालय मुंशी आरक्षक लखन गुप्ता का नाम भी मामले में शामिल किया गया था, लेकिन अदालत द्वारा प्रकरण खारिज किए जाने के बाद उन्हें भी राहत मिल गई।

विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने पर विचार किया जा रहा है।

संसद परिसर में तीखी जुबानी जंग, राहुल गांधी ने बिट्टू को बताया गद्दार दोस्त

नई दिल्ली, एजेंसी।

संसद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को संसद परिसर में उस समय राजनीतिक गर्मी बढ़ गई, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। पूरा घटनाक्रम कैमरों में कैद हो गया, जिसका दृश्य माध्यम सामाजिक मंचों पर तेजी से प्रसारित होने लगा।

घटना उस समय हुई जब कांग्रेस के सांसद निलंबित सदस्यों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी उनके साथ मौजूद थे। इसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, राहुल गांधी ने बिट्टू की ओर इशारा करते हुए कहा, ÷ये रहा गद्दार, इसका चेहरा देखो। इसके बाद उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, नमस्कार भाई, मेरे गद्दार दोस्त चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आ जाओगे।

राहुल गांधी की इस टिप्पणी से रवनीत सिंह बिट्टू नाराज हो गए। उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार करते हुए पलटवार किया और कहा, ÷देश के दुश्मन3। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक तीखी बहस होती रही, जिससे संसद परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया।

उल्लेखनीय है कि रवनीत सिंह बिट्टू पूर्व में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के चलते राहुल गांधी की टिप्पणी को दल-बदल की राजनीति और पुराने राजनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है।

इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की भाषा और आचरण पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से इसे राजनीतिक बयानबाजी और उकसावे की कार्रवाई बताया गया है।

हेलमेट से हमला कर कारोबारी की हत्या

नई दिल्ली।

राजधानी दिल्ली में देर रात एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। कनॉट प्लेस क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद एक डिलीवरी कर्मचारी ने हेलमेट से हमला कर एक कारोबारी की जान ले ली। पुलिस के अनुसार हमले में घायल कारोबारी की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी शिवम गुप्ता (36) के रूप में हुई है। बताया गया है कि 2 जनवरी की रात शिवम अपने एक मित्र के साथ कनॉट प्लेस स्थित एक भोजनालय में गया था। बाहर निकलने के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास ई ब्लॉक क्षेत्र में उसने एक डिलीवरी कर्मचारी से पानी मांगा, इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।

विवाद बढ़ने पर डिलीवरी कर्मचारी ने हेलमेट से शिवम के सिर पर कई वार किए, जबकि उसके दो अन्य साथियों ने शिवम के साथ लात-घूंसे से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल शिवम को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद से मृतक का परिवार सदमे में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हो सका

नई दिल्ली।

संसद में बुधवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी। लगातार व्यवधान के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित संबोधन भी नहीं हो पाया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार शाम पांच बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का उत्तर देना था। हालांकि, इससे पहले ही विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही।

सुबह से ही विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी और हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले सदन की कार्यवाही दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित की। इसके बाद स्थिति सामान्य न होने पर कार्यवाही दो बजे और फिर शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

शाम पांच बजे लोकसभा की बैठक दोबारा शुरू हुई, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं लिया। अंततः लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके चलते प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हो सका।

सभी औषधियों में हंसना सर्वोत्तम औषधि, यह बिना मूल्य के उपलब्ध होती है - पीएम मोदी

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आधारित एक प्रेरक संदेश साझा करते हुए हंसने को सबसे उत्तम औषधि बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सामाजिक माध्यम 'एक्स' पर एक संस्कृत सुभाषित साझा किया।

इस सुभाषित का आशय है कि सभी औषधियों में निस्संदेह हंसना सबसे श्रेष्ठ औषधि है, क्योंकि यह सहज रूप से बिना किसी मूल्य के उपलब्ध होती है और स्वास्थ्य व आनंद की वृद्धि करती है। प्रधानमंत्री ने लोगों से मुस्कुराते रहने का संदेश भी दिया।

साझा किए गए 53 सेकंड के दृश्य माध्यम में इस संस्कृत सुभाषित का हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भावार्थ समझाया गया है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर 2025 से भारतीय परंपरा के कालजयी ज्ञान को आधुनिक नीतियों और जनसंवाद से जोड़ने के उद्देश्य से समय-समय पर संस्कृत सुभाषित साझा कर रहे हैं। वे अपने भाषणों, 'मन की बात' कार्यक्रम और विभिन्न डिजिटल माध्यमों के जरिए संस्कृत सुभाषितों का उल्लेख करते रहे हैं।

संस्कृत सुभाषितों को सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री समकालीन शासन व्यवस्था को भारत की प्राचीन सभ्यतागत चेतना से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वे इन श्लोकों के माध्यम से विकास, स्थायित्व, लैंगिक समानता, नैतिक नेतृत्व और राष्ट्रीय दायित्व जैसे आधुनिक विषयों को सरलता से समझा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 दिसंबर को भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में संस्कृत भाषा की स्थायी प्रासंगिकता को भी रेखांकित किया था। उन्होंने दूरदर्शन के 'सुप्रभातम्' कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा था कि इस कार्यक्रम में प्रतिदिन संस्कृत सुभाषित प्रस्तुत किए जाते हैं, जो भारतीय मूल्यों और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोते हैं।

व्यापार समझौते से अमेरिका ने भारत को खरीद लिया - संजय राउत

नई दिल्ली, एजेंसी।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के जरिए अमेरिका ने भारत को खरीद लिया है और देश को अमेरिका के चरणों में डाल दिया गया है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों पर झूठ बोलने और दबाव में काम करने के आरोप लगाए।

संजय राउत ने बुधवार को कहा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित सरकार के सभी मंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए आयात शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत करने को सरकार बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन यह किस तरह की जीत है, यह जनता को बताया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले यह शुल्क लगभग तीन प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है।

राउत ने कहा कि इसके बावजूद अमेरिका के कृषि उत्पाद बिना किसी आयात शुल्क के भारत के बाजार में आएंगे। इनमें धान, फल, फूल, दूध और दुग्ध उत्पाद शामिल होंगे। अमेरिका का सस्ता माल भारतीय बाजार में आने से देश के किसानों पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसान खून-पसीना बहाकर उत्पादन करता है और उसी से सस्ता माल बाहर से आएगा, तो क्या किसान आत्महत्या करेगा।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किसी रहस्यमय तरीके से सरकार के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसके चलते देश के हितों से समझौता किया जा रहा है।

दूसरी ओर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते में कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि यह व्यापार समझौता अंतिम चरण में है और इसकी रूपरेखा स्पष्ट करते हुए जल्द ही भारतदूअमेरिका का संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। गोयल ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर समझौते को लेकर देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था।

जब तक हंगामा नहीं तब तक कोई भी बात स्वीकार्य नहीं

यही है शासन-प्रशासन की रीति-निती

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसूरी

अक्सर देखने में यह आता है कि जब तक कोई हंगामा ना हो जिला प्रशासन किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होता है। जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी हर बात को लेकर ढीला रवैया ही इख्तियार करते नजर आते है। ऐसे कई मामले है जिनमें अधिकारियों ने जमकर अपनी सुस्ती का मुजाहिरा किया। लेकिन जब बात हंगामें तक पहुंचती है तो फिर अधिकारी हर उस काम को कर गुजरते है जिसे वे पहले ही कर सकते थे। मगर शासन और प्रशासन की रीति-निती को देखा जाए तो यह साबित होता है कि, सीधी बातों से सरकारी ढर्रे के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मगर जब हंगामा होने की नौबत आती या हंगामा होता है तो फिर प्रशासन इस तरह से हरकत में आता कि, मानों कोई काम उसके लिए मुश्किल और असंभव नहीं है। जब स्थितियां बिगड़ती है तो फिर प्रशासन नचनियाओं की तरह सरपट नाचने भी लगता और गाने भी। उसके बाद वह अपनी प्रस्तुति के कसीदे भी खुद ही ऐसे गढ़ता मानों उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं और वह ऐसी स्थितियों में हमेशा तत्पर रहता है।

पिछले दिनों एक ऐसा ही मामला जिले में देखने को मिला। राणापुर ब्लॉक के ग्राम पाडवला की मॉडल के छात्र-छात्राओ ने स्कूल में पसरी अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार अपने प्राचार्य व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिकायत की थी। लेकिन लंबे समय से उनकी इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा था। इसके बाद मॉडल स्कूल पाडलवा के बच्चों ने हंगामेदार रास्ता इस्तेमाल किया। स्कूल के सभी छात्र -छात्राएं अपनी स्कूल से पैदल ही झाबुआ कलेक्ट्रोरेट करीब 16 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंच गए। जब ये बच्चे अपनी मांगों को लेकर पैदल झाबुआ के लिए निकले तो रास्ते में कई विभागीय अधिकारियों ने इन्हे रोकने की कोशिश की और कई आश्वानों के झुनझुने पकड़ाने की कवायदें की। लेकिन मॉडल स्कूल के छात्र-छात्राएं यह समझ चुके थे कि, अगर अभी अधिकारियों के हाथों से आश्वाशन का झुनझुना ले लिया तो फिर समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं है। अपने पथ पर अडिग मॉडल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने आश्वाशन के झुनझुने को ना पकड़ते हुए अपना सफर लगातार झाबुआ की तरफ जारी रखा। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्कूल प्राचार्य बच्चों की शिकायतों को गलत ही ठहराते रहे। लेकिन स्थानीय लोगों ने इस पर बच्चों का भरपूर समर्थन किया, क्योंकि वे लोग स्कूल की स्थिति से बखूबी वाकिफ थे। बच्चे 16 किलोमीटर का सफर कर कलेक्ट्रोरेट पहुंचे और यहां उन्होने अपनी मांगों को लेकर धरना तक दे दिया। हंगामेदार धरने के बाद उन्हे कलेक्टर से मिलने को बुलाया गया और खुद कलेक्टर ने उनकी बात सुनी। कलेक्टर के आश्वाशन के बाद यह बच्चे वापस लौट गए।

यहां एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि, क्या जो काम कलेक्टर ने किया वह इतना मुश्किल था कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इसे करने में असमर्थ थे। या फिर मॉडल स्कूल के प्राचार्य की आवाज इतनी कमजोर थी कि, उनकी सुनवाई विभाग में नहीं हो रही थी। आखिर यह किस तरह का खेल था कि, पाडलवा मॉडल के बच्चों की आवाज पहले शिक्षा विभाग और प्राचार्य या उच्चाधिकारियों तक नहीं पहुंच रही थी। मगर जब बच्चों ने हंगामा किया और 16 किलोमीटर का मार्च निकाल कर शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन की आबरू तार-तार कर दी तब कहीं जाकर उन्हे इन्साफ मिला। 30 जनवरी को हुए इस हंगामें के बाद मंगलवार को मॉडल स्कूल के छात्र-छात्राओं की मांग पूरी होना शुरू हो गई। पहली खेप में उन्हे खेल सामग्री उपलब्ध करा दी गई। अब आगे उम्मीद यही है कि, समय रहते बची मांगे भी छात्र-छात्राओं की पूरी हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह तय है कि, ये बच्चे फिर वही राह इख्तियार करेंगे जो उन्होने पहले की थी।

यहां गौर करने की बात यह है कि, यह कोई पहला मामला नहीं है जब स्कूली छात्रों ने सड़क पर उतर कर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की इज्जत तार-तार कर दी। बल्कि जिले में ऐसे कई मामले देखने को मिलते है जो लंबे समय तक अधिकारियों की ढीलाई के कारण एक दिन हंगामें के रूप में जिला मुख्यालय पर देखने को मिल ही जाते है। इससे पहले भी ऐसी ही किसी समस्या को लेकर अगराल मॉडल स्कूल के बच्चों ने लगभग इतना ही पैदल सफर कर जिला मुख्यालय तक सड़क माप दी थी। जिसके बाद ही उनकी समस्याओ का निराकरण हो पाया था। यह तो हुई बच्चों और शिक्षा जगत से जुड़ी बात लेकिन इसके अलावा भी कई मामलों में इस तरह के हंगामें देखने को मिले है। अभी ताजा मामले में ही सजेली नानिया साथ में हुए गौ-हत्या कांड को लेकर भी यही स्थिति देखने को मिली। घटना के डेढ़-दो माह गुजरने के बाद भी प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा था। जब 27 जनवरी को बंद व प्रदर्शन का आव्हान हुआ तो प्रशासन फिर सख्ते में आया और उसने ताबड़तोड़ इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। धरना प्रदर्शन व बंद के बाद जिला प्रशासन ने आगे भी कड़ी कार्रवाई का आश्वाशन दिया और ज्ञापन की मांगों को पूरा करने की भी बात कही। और भी ऐसे कई मामले है जिनमें प्रशासन चाहता तो पहले ही कार्रवाई कर देता। लेकिन यह प्रशासन की आदत सी बन गई है कि, जब तक कोई दबाव नहीं आता वह मामलों को ठंडे बस्ते में ही डालने की फिराक में रहता है। हंगामों के बाद की स्थिति और पहले की स्थिति पर नजर दौड़ाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि, जिस तरह से कुंभकरण को नींद से जगाने के लिए भारी भरकम नगाड़े और शंख बजाए जाते थे उसी तरह जिले की जनता और विद्यार्थियों को भी प्रशासन को कुंभकरर्णी नींद से जगाने के लिए हंगामा करना पड़ता है।

सवाल यह भी है कि, हर काम कलेक्टर तक पहुंचने के बाद ही क्यों अंजाम तक पहुंचता है। बात कोई भी हो लेकिन अब जिले की जनता का विश्वाश प्रशासनिक तंत्र से उठता जा रहा है। जिले का हर फरियादी सीधे तौर पर अब कलेक्टर से ही मिलकर अपनी समस्या का समाधान क्यों चाहता है.. ? सीधी और सच्ची बात यही है कि, नीचले स्तर पर अब आमजन की कोई सुनवाई होती दिखाई नहीं देती और यही कारण आवेदकों और फरियादियों को कलेक्टर तक पहुंचने के लिए मजबूर करता है। अब सवाल जिला कलेक्टर से भी है कि, क्या आपकी अपने अधिनस्त अधिकारियों पर किसी तरह की कोई नकेल नहीं है या फिर कोई भी अधिनस्त आपके आदेश-निर्देशो को तवज्जो नहीं देता...? क्यों जिले का हर आवेदक आप तक पहुंचना चाहता है...? क्या आपके अधिनस्त अधिकारी इतने निकम्मे हो गए है कि, वे जिले की जनता या विद्यार्थियों की एक भी बात कान पर नहीं धरते...? क्या जिले की आम जनता का विश्वाश अब सिर्फ कलेक्टर पर ही रह गया है...? अगर यह सारे प्रश्न सही है तो फिर जिले में किसी को तो शर्म आनी चाहिए। अगर भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहती है तो फिर आने वाले समय में जिले की जनता को यही हंगामेदार रास्ता अपनाना पड़ेगा और हर रोज जिला प्रशासन की थू-थू प्रदेश व देश में होने लगेगी।

क्योंकि वर्तमान स्थितियां तो इसी तरफ इशारा करती दिखाई दे रही है। जब तक हंगामा नहीं तब तक किसी की कोई सुनवाई स्वीकार्य नहीं और यही जिले में शासन और प्रशासन की रीति और निती बनती दिखाई दे रही है।

लावारिस सांड की मृत्यु पर युवाओं ने पेश की सनातन धर्म की मिसाल

माही की गूंज, सारंगी, संजय उपाध्याय।

सनातन धर्म में 'प्राणिमात्र पर दया' के भाव को सर्वोपरि माना गया है, और इसी भावना का जीवंत उदाहरण आज ग्राम पंचायत सारंगी में देखने को मिला गाँव में एक सांड की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद, स्थानीय युवाओं ने न केवल अपनी आस्था का परिचय दिया, बल्कि एक अत्यंत सराहनीय और अनुकरणीय कार्य कर मानवता की मिसाल पेश की।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत सारंगी में एक सांड की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। अक्सर ऐसी स्थितियों में बेसहारा पशुओं की सुध लेने वाला कोई नहीं होता, लेकिन सारंगी के धर्मप्रेमी युवाओं ने इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझा।

सनातन धर्म की परंपराओं और जीव-दया के भाव को ध्यान में रखते हुए, गाँव के युवाओं ने एकजुट होकर सांड के पार्थिव शरीर का ससम्मान अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। युवाओं की इस टोली ने पूरे विधि-विधान और सेवा भाव के साथ इस कार्य को संपन्न किया। सनातन धर्म हमें हर जीव में ईश्वर का अंश देखना सिखाता है आज युवाओं द्वारा किया गया यह कार्य इसी विचारधारा का प्रतीक है कि, हमारे मन और मस्तिष्क में दया की भावना सदैव जीवित रहनी चाहिए। युवाओं के इस निस्वार्थ सेवा कार्य की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है ग्रामीणों का कहना है कि आज के दौर में जहाँ लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं, वहीं सारंगी के इन युवाओं ने बेजुबान पशु के प्रति जो सम्मान दिखाया है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है।

पंचायत और पुलिस ने किया अपना काम.... राजस्व विभाग निभाए अपनी जिम्मेदारी

आतंक का पर्याय बन चुके अतिक्रमण माफिया रामू नाथ को कलेक्टर ने किया जिला बदर

सरपंच रामकन्या मकोड, थाना प्रभारी निर्भयसिंह भूरिया व प्रभारी तहसीलदर अनिल बघेल ने रामू नाथ का निकाला पूरा कच्चा चट्ठा ओर की कार्रवाई।

माही की गूंज , पेटलावद।
राकेश गेहलोत

विगत एक वर्ष में पेटलावद थाना क्षेत्र के ग्राम बामनिया के सबसे चर्चित नाम अतिक्रमण माफिया जिसने कई लोगों की निजी ओर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर पुलिस और प्रशासन की नाक में दम कर रखा था। लगातार विवादों के बाद पुलिस ने रामू नाथ की पूरी कुंडली तैयार की। जिसके बाद रामू नाथ के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। पेटलावद पुलिस द्वारा रामू नाथ के आपराधिक प्रकरणों के साथ-साथ राजस्व न्यायालय ओर न्यायालय में अतिक्रमण के चल रहे प्रकरणों की फाइल तैयार कर पुलिस अधीक्षक झाबुआ के पास भेजी। जहां से प्रकरण की समीक्षा ओर गंभीरता को देखते हुए रामू नाथ को जिला बदर करने हेतु फाइल पुलिस अभिमत के साथ कलेक्टर कार्यालय भेजी गई।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा रामू नाथ सहित तीन आदतन अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए।

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर नेहा मीना ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क, ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में लोक-शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से तीन आदतन अपराधियों के विरुद्ध छह माह की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार कैलाश उर्फ भोला पिता भेरूलाल भाटी निवासी सिर्वी मोहल्ला पेटलावद, रामुनाथ पिता नाथुनाथ कालबेलिया निवासी बामनिया तथा लोकेन्द्र उर्फ लोकेन्द्रसिंह उर्फ लच्छु पिता निरंजनसिंह चौहान निवासी दिलीप गेट झाबुआ को आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर झाबुआ जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिले धार, रतलाम, आलीराजपुर एवं बड़वानी की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। यह प्रतिबंध छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में बिना सक्षम न्यायालय के पूर्व लिखित अनुमति के उक्त क्षेत्रों में प्रवेश निषेध रहेगा। पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अनावेदक रामुनाथ पिता नाथुनाथ कालबेलिया निवासी बामनिया वर्ष 2002 से भूमि विवाद, मारपीट, अवैध कब्जा तथा दुर्लभ जाति के सर्पों के अवैध व्यापार जैसे अपराधों में संलिप्त रहा है। हाल ही में इसके विरुद्ध थाना पेटलावद एवं थाना थांदला में गंभीर अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। इसके कृत्यों से आमजन भय के वातावरण में जीवन यापन कर रहे है। अनावेदक की निरंतर आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए इसे भी जिला एवं सीमावर्ती जिलों से जिला बदर किया जाना आवश्यक पाया गया। उपरोक्त तीनों अनावेदकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क, ख) के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई है, ताकि जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनी रहे।

ग्राम पंचायत ने की थी पहल

ग्राम पंचायत बामनिया की सरपंच रामकन्या मखौड़ ने रामू नाथ द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि सहित अन्य शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जा कर रखा था जिसकी शिकायते पूर्व में की गई थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्राम पंचायत को कई सरकारी निर्माण कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नल-जल जैसी व्यवस्था रामू नाथ के अवैध कब्जे के चलते असुरक्षित हो रही थी । ग्राम पंचायत द्वारा 15 अगस्त 2025 की विशेष ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अवैध रूप से किए ग्राम पंचायत ओर शासकीय भूमियों से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही कर पेटलावद तहसील न्यायालय में मय प्रमाण लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी ।जिसकी जांच वर्तमान में भी जारी है। सरपंच रामकन्या मखौड़ ने पुलिस कार्यवाही ओर जिला कलेक्टर नेहा मीना के निर्णय का स्वागत किया तथा धन्यवाद देते हुए कहा कि, रामू नाथ लगातार ग्राम में आतंक का पर्याय बना हुआ है ओर न केवल शासकीय बल्कि लोगों की निजी जमीनों पर जबरन कब्जा कर उनको ओन-पौने दाम पर खरीद कर अपने नाम करवा लेता है। कई जमीनों पर कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति रोज बन रही थी जिससे ग्राम का माहौल खराब हो रहा है। जिसके लिए कड़ी कार्रवाई रामू नाथ के लिए जरूरी थी।

कलेक्टर नेहा मीना ने रामू नाथ के आतंक के रिकॉड को देखते हुए जारी किया जिला बदर का आदेश।

पुलिस ने निभाई अपनी भूमिका

लगातार जमीनी विवाद ओर अपराधिक रिकॉड होने के बाद भी रामू नाथ का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा था। थाना पेटलावद के थाना प्रभारी निर्भयसिंह भूरिया द्वारा लगातार रामू नाथ को समझाइश दी जा रही थी लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं था। जिसके बाद थाना प्रभारी निर्भयसिंह भूरिया ने रामू नाथ का पूरा इतिहास खंगाला और जिला बदर के लिए कार्यवाही कर फाइल को जिला अधीक्षक कार्यालय की ओर भेजी।

अब राजस्व की बारी

ग्राम पंचायत बामनिया ओर पुलिस अपनी भूमिका इस मामले में बखूबी निभाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई है लेकिन आज भी रामू नाथ के कब्जे से कई शासकीय भूमियों ओर अवैध निर्माण आज किए हुए है, जिसकी शिकायत राजस्व विभाग को की जा चुकी है। शिकायत के बाद तहसीलदार अनिल बघेल द्वारा सात पटवारियों की टीम बनाई थी जिसको रामू नाथ द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण की जांच करनी थी। एसआईआर के चलते जांच दल केवल एक बार ही जांच के लिए आ पाया वो भी सिर्फ अतिक्रमण चिन्हित कर लौट गया।

तहसीलदार अनिल बघेल ने बताया कि, जांच कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और शासकीय व पंचायत की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। निजी भूमियों पर कब्जे को लेकर श्री बघेल ने कहा कि, शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत ओर पुलिस के बाद अब राजस्व विभाग को चाहिए कि, रामू नाथ के कब्जे की सारे अतिक्रमण हटा कर शासकीय भूमियों पर कब्जा कर आतंक फैलाने वालों को कड़ा संदेश देना चाहिए।

अपराधिक पृष्ठभूमि व अतिक्रमण माफिया रामू नाथ हुआ जिला बदर।

गूंज ने निभाई अपनी भूमिका

रामू नाथ के आतंक ओर झूठी शिकायते ओर महिलाओं को आगे करके किसी भी व्यक्ति को डरा-धमका कर हर बार बचने में कामयाब रहता है। ऐसे में गूंज ने रामू नाथ के आतंक का पूरा कच्चा चिट्ठा बेबाकी के साथ प्रकाशित कर मामले को उजागर किया। इस दौरान रामू नाथ ने गूंज प्रतिनिधि पर झूठे आरोप ओर कई झूठी शिकायतें अगल-अलग अधिकारियों को कर परेशान करने का भी पूरा प्रयास किया । गूंज द्वारा प्रत्येक खबर शिकायत आधारित होकर प्रामाणिक रूप से प्रकाशित की ओर शिकायत की जांच में पुलिस का पूरा सहयोग किया । जिससे रामू नाथ का गूंज की आवाज दबाने की सारी कोशिशें नाकाम रही । रामू नाथ द्वारा कैसे इतने कम समय में सैकड़ों बीघा जमीन खरीद कर, कैसे अचूक संपत्ति का मालिक बना इस पर भी जांच होती है तो कई बड़े खुलासे होने की संभावनाओ से इंकार नहीं किया जा सकता।

देवर की शादी में नाचने व रील बनाने से रोका तो नवविवाहिता ने पति का गला घोंट की हत्या

क्या नाबालिग विवाहिता ही हत्यारी या कोई बड़ा षड़यंत्र या फिर मामले में और भी कोई हत्यारा...?

माही की गूंज, झाबुआ/ खवासा।

झाबुआ जिले की पुलिस सही को गलत और गलत को सही बनाने वाली कार्य प्रणाली के चलते अपनी विश्वसनीयता खो बैठी है। इसलिए पुलिस किसी मामले या घटना का खुलासा करती है तो अब आम जनता को उस खुलासे पर पूरा भरोसा नहीं होता है। ओर अगर बात थांदला पुलिस की आए तो वो कुछ भी अपनी सुल्तानी कर सकती है जिसमे वो हर प्रकार की महारत हासिल कर चुकी है, जिसका हम पूर्व में भी कई बार खुलासा कर चुके है।

इसी कड़ी में थांदला थाने की खवासा चौकी के ग्राम नारेला में 28 जनवरी को एक हत्या का मामला आया। जिसमे कैलाश पिता रायचंद्र माल (25) का शव उसके घर में से मिला। मामले में पुलिस ने दूसरे दिन ही खुलासा करते हुए झाबुआ एसपी ने पत्रकार वार्ता रखी और बताया कि, पति कैलाश अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करता था एवं हत्या के पूर्व संध्या परिवार में पति के छोटे भाई की शादी का समारोह था।

जिसमें पत्नी रानू डांस कर रही थी जिसे रोका एवं मोबाइल पर रील बनाने के लिए भी पति रोकता था। उक्त बात से पत्नी को गुस्सा आया और आपसी पति-पत्नी में तीखी बहस हुई। रात्रि में घर में रखी पगड़ी की रस्सी बनाई तथा सोये हुए कैलाश का गला पगड़ी की रस्सी से घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करने की बात सामने आई उसके बाद उक्त खुलासा किया। खुलासे में यह भी सामने आया कि, कैलाश की पत्नी ने यूट्यूब पर हत्या करने का आईडिया लिया।

पुलिस ने पति की हत्यारी विवाहिता की पुष्टि भी नाबालिक के रूप में की है। वही बताया जा रहा है कि, कैलाश का विवाह रानू से 7 माह पूर्व ही हुआ था। तथा पुलिस ने हत्यारी पत्नी की नाबालिक होने की पुष्टि के साथ यही खुलासा किया कि, पति, पत्नी पर शंका करता था तथा रील बनाने से रोकता था और हत्या के पूर्व पत्नी को नाचने से पति ने रोका इस बात पर बहस हुई और पत्नी ने पति की हत्या कर दी।

लेकिन आमजन में पुलिस अपने विश्वास को खोते नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस के खुलासे में नाबालिक विवाहिता पत्नी ही सिर्फ हत्यारी होगी यह किसी को विश्वास नहीं आ रहा है। और विश्वास न होने का कारण भी यही है जैसे कि, हत्या में एक महिला वह भी नाबालिक और शादी के महज 7 माह में ही पत्नी पर शंका और रील बनाने व नाचने की बात पर रोकने पर हत्या का कदम उठा लेना...? यह किसी के मन को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। लोगों की दबी जुबान व चर्चाओं में यही अपने - अपने अनुमान लगाए जा रहे हैं कि, पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप पति लगाता था तो तय है यह बात परिवार में भी किसी को सार्वजनिक की होगी। और अगर यह बात दबाई गई हो तो और कोई अन्य बात भी हो सकती है। वही यह भी आकलन लगाया जा रहा है कि, अगर पति को शंका थी तो तय है हत्या का आईडिया यूट्यूब से लिया तो ऐसे में यह हत्या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा होकर प्रेमी या अन्य के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है... षड्यंत्र में यह भी हो सकता है कि, षड्यंत्रकारी ने यह षड्यंत्र रचा हो कि, महिला नाबालिक है और हत्या के बाद भी खुलासा होने पर महिला अपना जुर्म कबूल कर भी लेती है तो उसे न्यायालय से जल्द राहत मिलकर वह बाहर आ सकती है। और सहलिप्त षड्यंत्रकारी, महिला को छुड़ाने में अपना पूरा प्रयास करेंगे। इसी बात का संदेह जताया जा रहा है ओर आश्वस्त होकर महिला ने पूरा आरोप अपने ऊपर ले लिया होगा की चर्चा हो रही है। महिला और वह भी नाबालिक होकर इतना बड़ा हत्या का षड्यंत्र व साहस अकेली नहीं कर सकती है! और न ही इस प्रकार की घटना पहले क्षेत्र में सामने आई है की भी चर्चा हो रही है।

ऐसे में मांग की जा रही है कि, पुलिस को अब भी हर बिंदु पर इस घटना की जांच करने की आवश्यकता है।

क्या यह शादी लड़की की बिना मर्जी से तो नहीं हुई थी...?

शादी हुई तो 7 माह में ही रील व नाचने पर रोक-टोक का आखिर क्या कारण...?

तथा पति अगर शंका करता था तो पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ संपर्क था क्या जो शंका का कारण था..? तो वह व्यक्ति कोन...?

आदि बिंदुओं पर पुलिस को गहनता से जांच कर एक बार फिर मामले का खुलासा करना चाहिए।

वहीं दूसरी बात यह कि, उक्त खुलासे में नव विवाहित हत्यारी पत्नी को नाबालिक घोषित करने के साथ ही एक बार फिर प्रशासन पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं और जिले में कितने भी प्रयास कर ले नाबालिक विवाह रोकने का, पर प्रशासन नाकामयाब ही रहा है। ओर क्षेत्र में प्रति वर्ष बिना किसी रोक-टोक के नाबालिक की शादियां हो रही है।

प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद-पत्र सौंपा

माही की गूंज , झाबुआ डेस्क।

धन्यवाद-पत्र देते हुए डॉ नरेश माही।

बांसवाड़ा। राज्य सभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया से दिल्ली में ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान के संयोजक डॉ नरेश माही ने भेंट की । उक्त मुलाकात में उच्च शिक्षा में समानता बढ़ाने के लिए किये गए प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री के नाम एक धन्यवाद-पत्र दिया। पत्र में बताया गया कि, केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 लागू किया। यह नियम न केवल जातिगत और लैंगिक भेदभाव को रोकने का महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के वि?द्यार्थियों के लिए समान अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी ऐतिहासिक पहल है।

इस निर्णय से केवल शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, बल्कि समाज में समानता और समावेशिता का संदेश भी फैलेंगा, जिससे हमारे कमजोर वर्ग के युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने का भरोसा मिलेगा।

इस महत्वपूर्ण कदम के लिए ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान द्वारा प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रेषित करता हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे निर्णय सभी वर्गों के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करने में मार्गदर्शक होंगे।

इस नियम को डॉ नरेश माही ने आईआईटी, आई आईएम और एम्स में भी लागु करने की मांग की स राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया ने बताया कि, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया जायेगा। उक्त जानकारी ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान के प्रवक्ता डॉ लोकेन्द्र गुर्जर ने दी।

खुशी चाणोदिया ने पास की 'ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन

माही की गूंज, पेटलावद।

नगर की होनहार बेटी सुश्री खुशी चाणोदिया ने कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। खुशी ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। उनकी इस सफलता से न केवल उनके परिवार में हर्ष का माहौल है, बल्कि पूरे क्षेत्र और समाज का मान बढ़ा है। खुशी पेटलावद के वरिष्ठ श्रावक सोहनलाल चाणोदिया की सुपौत्री एवं कीर्तिश चाणोदिया की सुपुत्री हैं। खुशी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने दादाजी के आशीर्वाद, माता-पिता के मार्गदर्शन और अपनी निरंतर कड़ी मेहनत को दिया है। एक छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नगरवासियों ने उन्हें बधाई दी है। समाज के प्रबुद्धजनों का कहना है कि खुशी की यह उपलब्धि अन्य युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उनकी सफलता पर इष्ट मित्रों और परिजनों ने उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं की हैं।

खुले में फेकी जा रही मेडिकल वेस्ट

माही की गूंज ,करवड़।

झाबुआ जिले के ग्राम करवड़ में अवैध चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे अवैध तरीके से कार्य तो कर ही रहे हैं। लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं जिले में बायो मेडिकल वेस्ट कचरे के निस्तारण का कोई उचित बंदोबस्त नहीं होना या फिर जानकर भी अनजान होना। निजी चिकित्सक अवैध तरीके से बिना डिग्री के मनमाने तरीके से इलाज तो कर रहे हैं। वही करवड़-बामनिया रोड पर पहली पुलिया स्थित नाले में खाली बोतल व इंजेक्शन खत्म होने के बाद खुले में फेके जा रहे है। खेत के पास एक नाले में अवैध तरीके से उपयोग किए हुए इंजेक्शन व खाली बोतल पड़े हुए हैं, वहीं से नाला भी बहता है, जिससे कभी भी कोई बड़ा संक्रमण फैल सकता है। इस तरह अवैध तरीके से खुले में इस खतरनाक कचरे को फेंक रहे हैं। जिससे बीमारिया फैलने की आशंका है, वहीं नाले का पानी पशु भी पी रहे हैं जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस तरह के खुले में कचरा नहीं फेंकने के सख्त आदेश व निर्देश दे रखे है, लेकिन फिर भी प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए झोलाछाप चिकित्सक इस तरह से खुले में सामग्री फेंक रहे हैं । जिससे कभी भी कोई गंभीर संक्रमण या बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है।

सबको पानी पिलाने वाले काका अपनी मौत से जंग हार गए

माही की गूंज, भामल।

मौत कब ओर किसको अपने आगोश में ले ले यह कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही वाकिया ग्राम पंचायत भामल में पानी सप्लाई करने वाले दिलीप(काका) डामोर के साथ हुआ जो अब नहीं रहे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस अपने घर पर ही ली। जानकारीनुसार सुबह जैसे ही उठे तो अपनी दिनचर्या की तथा ठंड के चलते अलाव के पास अपने परिवारजनों के पास बैठे थे। जहाँ पत्नी के साथ ही पोते-पोती भी अलाव के पास बैठे थे उसी दौरान पूरी तरह से स्वस्थ दिलीप काका को घबरावट के साथ पसीना आने लगा, जिसके बाद उन्होंने बच्चों से पानी मांगा। साथ ही कहा कि मुझे पंखा चला देवे मुझे गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। परिवार के सदस्यों ने उनको पास ही घर के समीप खटिया पर ले जाकर सुला दिया। जैसे ही खटिया पे सुलाया उसके बाद उनकी अंतिम सांस टूट गई। तथा परिवार में चीख-पुकार मच गई कि, अचानक ऐसा क्या हुआ की दीपला काका की मौत हो गई। जैसे ही खबर गांव में पहुंची तो पूरा गांव हथ परत रह गया। बतादे कि, पूरे ग्राम भामल में उनके द्वारा ही सार्वजनिक कुए से ब्हेम सप्लाई दिया जाता था, जो नल का पानी ग्रामीण पीते थे। दीपला काका की अचानक हुई मौत पर कोई यकीन नही कर पा रहा है। उकनी मौत से परिवार एवं ग्राम में शोक छा गया।

सरकार ओर पुलिस के प्रयास हो रहे विफल

सेवानिवृत्त लाइनमेन से साइबर ठगो ने ठगे 8 लाख रुपए

माही की गूंज, बरवेट।
जगदीश प्रजापत

साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ओर पुलिस लगातार लोगो को जागरूक करने के अभियान चला रही है। वही लाखों-करोड़ो के विज्ञापन, नुक्कड़ नाटक सहित हर प्रकार से प्रचार-प्रसार में खर्च किए जा रहे। इसके बावजूद भी लोग इन साइबर ठगो की बातों में उलझ कर अपनी जमा पूंजी लुटा देते है। अनपढ़ तो ठीक पढ़े-लिखे लोग भी इन ठगो का चारा बन जाते है।

ताजा मामला झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ठगों ने 'डिजिटल अरेस्ट' और 'मनी लॉन्ड्रिंग' का खौफ दिखाकर एक सेवानिवृत्त विद्युत लाइनमैन की जीवन भर की जमापूंजी पर डाका डाल दिया।

खाते से फर्जी लेन-देन का दिया झांसा

बरवेट निवासी पीड़ित सेवा निवृत्त लाइनमेन पुरुषोत्तम पाटीदार को शुक्रवार को मोबाइल नंबर 82890 75940 से एक कॉल आया। जिसमें फोन करने वाले ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए दावा किया कि, लाइनमेन का मुंबई में एक बैंक खाता है, जिसका संबंध किसी इस्लामिक संगठन से जुड़ा है। ठग ने पीड़ित को डराते हुए कहा कि, उस खाते से 2 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन-देन हुआ है, जिसके चलते उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर एफआईआर कर ली गई है। पीड़ित को पूरी तरह अपने जाल में फंसाने के लिए ठगों ने उनके आधार कार्ड की जानकारी साझा की और व्हाट्सएप पर बैंक स्टेटमेंट के साथ फर्जी एफआईआर की कॉपी भी भेज दी।

ठगो के झांसे में आ गए लाइनमेन साहब, मामला निपटाने के 20लाख की मांग

जिस तरह ठगो ने सेवानिवृत लाइनमेन पर दबाव बनाया, लाइनमेन साहब इस मनोवैज्ञानिक दबाव और जेल जाने के डर से घबराए ओर तनाव में आ गए। ठग ने मामला रफा-दफा करने के बदले 20 लाख रुपए की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए ,लाइनमेन साहब पैसे की जुगाड में लग गए।

एफडी तुड़वा कर जमा किए पैसे

इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करने के लिए पाटीदार जी ने घर से 5 किलोमीटर दूर सारंगी स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 15 लाख रुपए की एफडी तुड़वा दी। इस दौरान ठग लगातार मोबाइल नंबर 97313 82283 से उन्हें निर्देश देते रहे और किसी को भी इस बारे में बताने से सख्त मना किया। शाम करीब 4 बजे जब बैंक प्रबंधक ने इतनी बड़ी राशि दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का कारण पूछा, तो डरे हुए लाइनमेन ने सच छिपाते हुए इसे जमीन सौदे के लिए भाई को भेजी जाने वाली रकम बता दिया। बैंक मैनेजर द्वारा एक साथ पूरी राशि भेजने में असमर्थता जताने पर, पहली किस्त के रूप में 7,99,672 रुपए कोलकाता स्थित प्व्ब्प् बैंक के खाता संख्या 000605036748 में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए गए। शाम को जब पाटीदार जी घर लौटे और उनके पुत्र मनोज ने पिता को भारी तनाव में देखा, तब पूछताछ के दौरान इस पूरी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। इसके बाद परिजन तत्काल रायपुरिया थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई।

हैरान करने वाली बात यह है कि,ठगी को अंजाम देने के बाद भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि, वे शनिवार सुबह तक पीड़ित को फोन कर बाकी की राशि भेजने के लिए धमकाते रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अब तक नहीं लगा कोई सुराग

साइबर ठग बेहत ही शातिर ओर टेक्नोलोजी का भरपूर उपयोग करते है जिसको आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है लेकिन ठगी करने वालो के मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर होने के बाद भी पुलिस इन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। फिलहाल मिली जानकारीनुसार पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही हैं और खबर लिखे जाने तक किसी प्रकार की सफलता पुलिस को नहीं लगी है।

सतर्क रहने की जरूरत

साइबर ठगी के लिए ठग कई प्रकार से नई-नई योजना बना कर लोगो को ठगने की कोशिश करते है। तथा किसी न किसी तरह का डर ओर भय पैदा कर आपसे मोटी रकम एठ लेते हैं। जब तक आप इनकी चालाकियों को समझ पाते है तब तक ये इनका काम करके निकल जाते है। पुलिस भी इस प्रकार के मामलो में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि ठगी को अंजाम देने वाले अज्ञात ओर हजारों किलोमीटर दूर बैठ कर अपना काम करते है। इसलिए किसी भी फर्जी काल ओर डराने धमकाने वाले फोन काल पर तुरंत जवाब देने की बजाए इसकी सूचना परिवार ओर पुलिस को देकर हर प्रकार की ठगी से बचा जा सकता है।साइबर ठगी से बचने का एक मात्र उपाय सतर्कता ही है जो आप ओर हम सबको स्वयं को दिखानी होगी ।

संपादकीय

अति आशावाद से बचें

देश में आम बजट से पहले सामने आने वाले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला व गतिशील बनाने पर बल दिया गया है। यह सर्वेक्षण उन चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है, जिनके लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद दर यानी जीडीपी के 7.4 रहने का भरोसा जताया गया है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास वृद्धि दर के 6.8 से 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान में सीमापरक तनाव, व्यापार में व्यवधान और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता को भी ध्यान में रखा गया है। निश्चित रूप से यह सावधानीपूर्वक दर्शाया गया आशावादी दृष्टिकोण घरेलू मांग, उपभोग और निवेश की मजबूती को ही दर्शाता है। इसके बावजूद कि तमाम बाहरी जोखिम विद्यमान हैं, मसलन टैरिफ को लेकर आपूर्ति श्रृंखला में तनाव व देश की अपेक्षाओं का संतुलन बनाना शामिल है। यह सार्थक है कि सर्वेक्षण यथार्थवाद को नजरअंदाज नहीं करता है, जो यह भी दर्शाता है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पूंजी प्रवाह व मुद्रा की ताकत से ही सफलता सुनिश्चित नहीं होती। यह भी हकीकत है कि एआई जैसी नई तकनीकों से होने वाले लाभ असमानता को ही बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसके लिये भी सहायक मानव संसाधन और विनियामक ढांचे की जरूरत होती है। खासकर भारत जैसे देश में जहां श्रम शक्ति का बाहुल्य है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश होने का लाभ उठाएं। इसके लिये कौशल विकास को प्राथमिकता देने की सख्त जरूरत है, जिससे हम गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों के जरिये विश्व में आर्थिक स्पर्धा का मुकाबला कर सकें। ये कदम हमारे निर्यात बढ़ाने में भी सहायक हो सकते हैं। कालांतर में ये हमारे व्यापार घाटे को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है।

इसमें दो राय नहीं है कि हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के जरिये एक महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वदेशी अभियान को तरजीह देने से लेकर रणनीतिक लचीलेपन और रणनीतिक अनिवार्यता भारत की आर्थिक क्षमता की परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिये जरूरी है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं की साख को अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जाए। निस्संदेह, विश्व में भारतीय उत्पाद 'खरीदने के बारे में सोचने' से स्थिति को 'बिना सोचे भारतीय उत्पाद खरीदने' वाली सोच विकसित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इस स्थिति के लिये हमें विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता की सख्त जरूरत होगी। निस्संदेह, हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ संपन्न हुए ऐतिहासिक समझौते को लेकर अर्थव्यवस्था में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसके अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से लटके हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। सर्वेक्षण में इस बाबत कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में इस एफटीए के सिरे चढ़ने की उम्मीद है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ आम आदमी को कितना मिलता है। सवाल यह भी है कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ आम आदमी के जीवन को बदलने में कितना मददगार होगा। एआई और तकनीक क्रांति के दौर में भारतीय विपुल श्रम शक्ति का बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है। भारत दुनिया में सबसे युवा श्रम शक्ति वाला देश है तो क्या हम उनकी योग्यता व क्षमता के अनुरूप रोजगार देने में सक्षम होंगे, ताकि वे विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दे सकें। जरूरत इस बात की है कि देश में बेरोजगारी की दर कम हो और युवाओं के विदेश पलायन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये पहल की जाए। वहीं दूसरी ओर फिसलन वाली जमीन पर चलते हुए सर्वेक्षण में दो दशक पुराने सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव की मंशा जतायी गई है। निस्संदेह, ऐसे किसी बदलाव का आधार तार्किक होना चाहिए।

राज्यपालों की भूमिका पर फिर खिंची तलवारें

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक विधानसभाओं में राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव की खबरें इस साल भी आई हैं। ऐसा किसी न किसी रूप में पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। वर्तमान टकराव राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए अभिभाषणों के पढ़ने से जुड़ा है। प्रत्यक्षतः ऐसा अनजाने में नहीं हो रहा है। इन मामलों से जुड़े सभी पक्ष संवैधानिक व्यवस्थाओं और उनसे जुड़ी मर्यादा-रेखाओं से भली भांति परिचित हैं। राज्यपाल जानते-समझते हैं और राज्य सरकारें भी। तब ऐसा क्यों होता है?

इन राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपालों के रिश्ते काफी समय से तनावपूर्ण रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कई बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होने वाले राज्यपालों के 'एट होम' कार्यक्रमों का बहिष्कार कर चुके हैं। मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के बीच सीधा संवाद बहुत कम है। इस वक्त तो चुनाव करीब हैं, इसलिए माहौल में वैसे ही गर्मी भरी है।

दक्षिण के जिन तीन राज्यों में विवाद खड़े हुए हैं, उनमें इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही पार्टियों की सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार के विरोध में हैं। ऐसे विवाद होते ही तभी हैं, जब केंद्र और राज्य की सरकारों का आपसी विरोध हो। बंगाल और पंजाब में भी इससे मिलते-जुलते प्रकरण हुए हैं। राज्यपालों या राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित सरकारों द्वारा तैयार किए गए भाषणों या विशेष संबोधनों को हूबहू पढ़ना एक संवैधानिक परंपरा है। यह ब्रिटिश परंपरा है, जिस पर आधारित भारत की संसदीय प्रणाली में भी उन्हीं परंपराओं के पालन की उम्मीद की जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ, जब ब्रिटिश राजा या रानी ने आधिकारिक भाषण को लेकर ना-नुकुर की हो।

देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बीच बहुत से मामलों में मतभेद थे, पर उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, जिससे संसदीय मर्यादा भंग हो। पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन ने 1998 के गणतंत्र दिवस संबोधन में कुछ बदलाव किया था। कुछ दूसरे मौकों पर भी उन्होंने प्रस्तावित मसौदों में संशोधन किए थे, ताकि भाषण का स्वर और संदेश उनके विचारों के अनुरूप हो। ऐसे मौके संसद से बाहर के वक्तव्यों में ज्यादा देखे गए।

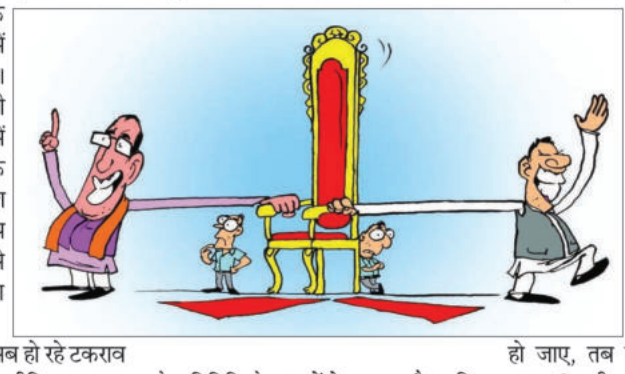

उनके दृष्टिकोण और अब हो रहे टकराव में फर्क है। अब इसने राजनीतिक टकराव की शक्ल ले ली है। मसलन कर्नाटक के प्रसंग को देखें, जहां राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने गत 22 जनवरी को विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए सरकार के तैयार भाषण की केवल तीन लाइन ही पढ़ीं और सदन से बाहर चले गए। गहलोत के इस कार्य को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने असंवैधानिक बताते हुए कहा, संविधान के अनुच्छेद 176 और 163 के तहत राज्यपाल को मंत्रिमंडल की ओर से तैयार पूरा भाषण पढ़ना चाहिए।

उधर राज्यपाल गहलोत सरकार के तैयार भाषण के पैरा नंबर 11 पर नाराज थे, जिसमें इनमें लिखा है कि केंद्र सरकार ने यूपीए काल में शुरू की गई मनरेगा योजना को कमजोर किया है। उसका बजट घटाया है, जिससे ग्रामीण रोजगार प्रभावित हुआ है। वस्तुतः यह केंद्र-राज्य संबंधों का महत्त्वपूर्ण पहलू है। सवाल है कि राज्य सरकारों के पास असहमति व्यक्त करने का क्या यही रास्ता बचा है? और क्या राज्यपालों के पास अपने विवेक का इस्तेमाल करने का अधिकार है?

सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकारों को संवैधानिक रूप से सीधे राज्यपाल के माध्यम से केंद्र की आलोचना करनी चाहिए? आखिरकार राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त संवैधानिक पद है। उसे राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, न कि राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में। पर क्या केंद्र सरकार को उनके माध्यम से राज्य सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए?

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के साथ लगातार टकराव चलने के कारण मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानमंडल के पहले सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण की प्रथा को समाप्त करने का समर्थन किया है। देश के आठवें राष्ट्रपति (1987-1992) आर वेंकटरमण ने राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधायिका के समक्ष पारंपरिक अभिभाषण की प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश कई बार की थी। वे इस औपनिवेशिक प्रथा को अनावश्यक और असंवैधानिक मानते थे।

फरवरी 1988 में संसद में अपना पहला अभिभाषण देने से पहले उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि 'मेरी सरकार' के स्थान पर 'सरकार' शब्द का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा, यह प्रथा ब्रिटिश विरासत का हिस्सा है और भारत में प्रासंगिक नहीं है। भारत का संविधान स्वयं जनता द्वारा संविधान सभा के माध्यम से बनाया गया था। ऐसे में देश के राष्ट्रपति द्वारा 'मेरी सरकार' कहना 'अनुचित' है। इस व्यवस्था को समाप्त करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अनुच्छेद 86 और 175 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास विधायिका को संबोधित करने का अधिकार तब भी बना रहेगा।

अतीत में कई राजनेताओं ने राज्यपाल का पद ही खत्म करने का सुझाव दिया है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि अभिभाषण की प्रथा समाप्त हो जाए, तब क्या यह विरोध खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्यपालों द्वारा विधानमंडलों से पास विधेयकों को रोककर रखने के प्रकरण का कोई पक्का समाधान नहीं निकला है। वस्तुतः समस्या संवैधानिक व्यवस्था में नहीं, हमारी राजनीतिक-संस्कृति में है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंतिम भाषण के दौरान यह ऐतिहासिक चेतावनी दी, 'संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे साबित हुए, तो संविधान भी बुरा साबित होगा।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की सफलता केवल इसके प्रावधानों पर नहीं, बल्कि इसे अमल में लाने वालों की नैतिकता और ईमानदारी पर निर्भर करती है।

ऐसे मतभेद और टकराव भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वह काफी कुछ वैसा ही कर रही है जैसा कांग्रेस ने दशकों तक किया। हम सैकड़ों साल पुरानी ब्रिटिश परंपराओं पर देश को चलाना चाहते हैं, तो पिछले कुछ दशकों की अपनी परंपराओं पर भी नज़र डालनी चाहिए। सच यह है कि जब दो विपरीत राजनीतिक विचारों की सरकारें केंद्र और राज्य में होती हैं, तब राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच प्रभावी संवाद चैनल होना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के लिए दोनों के बीच समन्वय की जरूरत होती है।

प्रमोद जोशी

मूल मुद्दा राज्यपाल पद का राजनीतिकरण है। इसका समाधान क्या है? एक काम फिर भी किया जा सकता है वह है सरकारिया और पंछी आयोग की सिफारिशें। सरकारिया (1983-88) और पंछी आयोग (2007-10) ने राज्यपाल की नियुक्ति में निष्पक्षता, मुख्यमंत्री से परामर्श, और सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चयन की सिफारिश की थी।

दोनों आयोगों का मुख्य उद्देश्य राज्यपाल पद को केंद्र के राजनीतिक एजेंट के बजाय एक तटस्थ संवैधानिक पद बनाना और राज्य के बाहर के व्यक्ति को नियुक्त करना है। इसके अनुसार, संविधान में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जा सकता है कि राज्यपालों की नियुक्ति से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया जाएगा।

ऐसा करने से राज्यपालों और निर्वाचित सरकारों के बीच सभी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाएगा। अलबत्ता महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों पर मतभेद को कम करने और वार्षिक संबोधन जैसी पारंपरिक प्रथाओं पर टकराव से बचने के लिए यह अच्छा प्रस्थान-बिंदु हो सकता है।

शिक्षा के जरिये रोजगार सृजन की दिशा में कदम

डॉ. शशांक द्विवेदी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026द्27 को सरकार 'नेक्स्ट जेनरेशन बजट' कह रही है। यह दावा केवल एक राजनीतिक नारा नहीं लगता, बल्कि बजट के प्रावधानों पर नज़र डालने से स्पष्ट होता है कि इसमें जेनरेशन जेड- यानी आज के युवा वर्ग- की शिक्षा, रोजगार, तकनीकी कौशल और रचनात्मक आकांक्षाओं को केंद्र में रखा गया है। आज का युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं है; वह स्किल-ड्रिवन, डिजिटल-नेटिव और क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बजट 2026-27 इसी बदले हुए युवा चरित्र को पहचानता है।

इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट पर ज़ोर। सरकार ने शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटने के लिए एक समग्र रणनीति अपनाई है। कौशल-आधारित शिक्षा, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों को बढ़ावा और यूनिवर्सिटी टाउनशिप की अवधारणा इस दिशा में अहम कदम हैं।

महत्वपूर्ण है कि केवल डिग्रियां युवाओं को रोजगार नहीं दिला सकतीं; उन्हें व्यावहारिक कौशल और उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यदि यह योजना ज़मीनी स्तर पर सही ढंग से लागू होती है तो यह भारत की युवा बेरोज़गारी की समस्या को कम करने में निर्णायक साबित हो सकती है। विदेश में पढ़ाई-लिखाई करने वाले छात्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का अनुभव चाहने वालों को राहत देने के लिए, सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत टीसीएस दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। इससे विद्यार्थी विदेश शिक्षा-अनुभव को अधिक किफ़ायती रूप से चुन सकेंगे, जिससे तकनीकी तथा ग्लोबल मौके और एक्सपोज़र मिलेंगे।

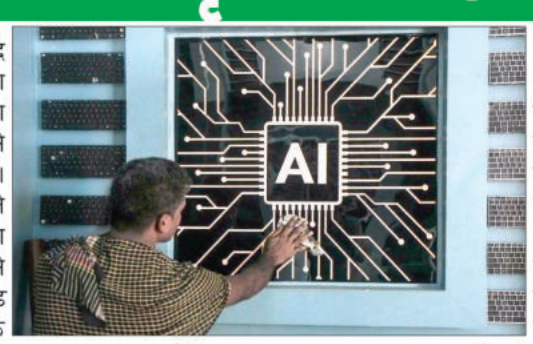

बजट में ऑरेंज इकोनॉमी यानी एनिमेशन, गेमिंग, डिज़ाइन, विज़ुअल इफेक्ट्स और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देना जेन जेड के लिए एक बड़ा संदेश है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि सरकार अब यूट्यूब, गेमिंग, एनीमेशन और डिजिटल स्टोरीटेलिंग को शौक नहीं, बल्कि कैरियर के रूप में देख रही है। इस कदम का व्यापक लक्ष्य यह है कि भारत 2030 तक लगभग 20 लाख एवीजीसी सेक्टर-विशेषज्ञों की आवश्यकता को पूरा करे, और उसे विश्व-स्तर के डिजिटल क्रिएटिव हब में बदल दे। यह कदम भारत के लाखों क्रिएटिव युवाओं को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग पर दिया गया ज़ोर इस बजट को भविष्य-उन्मुख बनाता है। आज की नौकरियां डेटा, एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम्स से जुड़ी हैं। बजट यह मानता है कि अगर भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहना है, तो युवाओं को इन्हीं क्षेत्रों में दक्ष बनाना होगा।

जेन जेड केवल नौकरी चाहने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि जॉब क्रिएटर बनने की आकांक्षा भी रखती है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग, पूंजीगत व्यय में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से नए अवसर पैदा होंगे। इससे युवा उद्यमियों को जोखिम लेने और नवाचार करने का भरोसा मिलेगा। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस)में कमी यह दर्शाती है कि सरकार वैश्विक शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोज़र को भी महत्व दे रही है। यह फैसला मध्यम वर्गीय युवाओं के लिए विशेष रूप से राहतकारी है। भारत का युवा वर्ग पहले से ही स्टार्टअप और नवोन्मेष (इनोवेशन) की ओर अग्रसर है कृयह बजट इन्हें संसाधन-समर्थक वातावरण देने की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। बजट ने खेलो इंडिया मिशन तथा खेल-इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार से युवाओं के खेल-प्रतिभा विकास को बढ़ावा दिया है। साथ ही पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र की डिजिटलाइजेशन तथा पर्यटन-संबंधित कौशल विकास योजनाएं भी युवा रोजगार सृजन को आगे बढ़ाती हैं।

कुल मिलाकर, बजट 2026द्27 केवल आज की जरूरतों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि आने वाले भारत की युवा-आधारित आर्थिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह बजट जेन जेड को बोझ नहीं, बल्कि भागीदार मानता है। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित योजनाएं काग़ज़ से निकलकर ज़मीन तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती हैं। यदि क्रियान्वयन मजबूत रहा तो यह बजट सचमुच भारत की अगली पीढ़ी को आत्मनिर्भर, कुशल और ग्लोबल नागरिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।

यह बजट शिक्षा से रोजगार तक का एकीकृत मार्ग प्रदान करता है। डिजिटल और तकनीकी कौशल को मुख्यधारा में लाता है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था और ऑरेंज इकोनॉमी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाता है। वैश्विक शिक्षा-अनुभव और रोजगार-सृजन के अवसरों को बढ़ाता है।

यह बजट केवल आज के युवाओं के लिए नहीं बल्कि अगले पांच दशक के युवाओं के लिए एक मजबूत आर्थिक ढांचा तैयार कर सकता है। साथ ही भारत को एक ग्लोबल तकनीकी-रचनात्मक शक्ति बनाने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम प्रतीत होता है।

श्रमिक-किसान कल्याण हो जीडीपी का पैमाना

भारत के नीति-निर्माता दुविधा में हैं। उनका कहना है कि कृषि क्षेत्र में जरूरत से बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उनके अनुसार, भारत के कृषि क्षेत्र की उत्पादकता, जिसको इसमें कार्यरत लोगों की संख्या के हिसाब से मापा जाता है, वह बहुत कम है। उनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रामीण इलाकों एवं खेतों से और लघु, 'अनौपचारिक' कारखानों और सेवा उद्यमों से भी निकालकर शहरों में लाया जाए ताकि उन्हें बड़े, 'औपचारिक' कारखानों एवं सेवा उद्यमों में काम पर लगाया जा सके।

समस्या यह है कि बड़े औपचारिक उद्यम पर्याप्त सुरक्षित नौकरियां और अच्छा वेतन नहीं दे रहे हैं। वे ज़्यादा लोगों को काम पर रखने, उन्हें अधिक तनख्वाह और सामाजिक सुरक्षा देने को तैयार नहीं हैं। इसकी बजाय, वे वेतन की लागत कम रखने के लिए अधिक 'लचीले' श्रम कानूनों की मांग कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या यह है कि सभी क्षेत्रों मसलन, विनिर्माण, सेवाएं और कृषि में नियोक्ता अपना उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंसानों के बजाय ज़्यादा मशीनरी और ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस मुख्य सुधार की ज़रूरत है, वह है व्यावसायिक उद्यम के ढर्रे और प्रचालन में सुधार। मज़दूर, चाहे वे खेतों में हों या कारखानों में, वे जिस उद्यमों में काम करते हैं उनके मालिकों की सोच होती है, उनके काम से हुआ मुनाफ़ा, उनका ही रहे और उनकी संपत्ति में इजाफा करे, न कि यह लाभ किसी वित्तीय निवेशक की संपत्ति बढ़ाने के काम आए। उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक पूंजीगत संपत्ति जैसे कि विनिर्माण उद्यम में मशीनें और खेती के लिए ज़मीन, उद्यम में काम करने वाले मज़दूरों की होनी चाहिए। मज़दूर अपने मालिक खुद हों और उन्हें स्टॉक मार्केट निवेशकों और सामंती ज़मींदारों की मल्कियत वाले कारखानों और खेतों में कर्मचारी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अपने काम से होने वाले मुनाफ़े का इस्तेमाल वह कैसे करेंगे, यह चुनने का अधिकार उन्हें होना चाहिए। अब चाहे तो अपने उद्यम में और अधिक निवेश करें या अपने परिवार के कल्याण और अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएं।

जैसा कि माइक बर्ड ने अपनी किताब 'द लैंड ट्रैप- ए न्यू हिस्ट्री ऑफ़ द वल्ड्र्स ओल्डेस्ट एसेट' नामक पुस्तक में बताया है कि भू-स्वामित्व में सुधार, जिसके तहत ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर उनके खेतों में काम करने वाले मज़दूरों को हस्तांतरित की गईं, उसकी बदौलत पिछले 50 सालों में जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन में छोटे किसानों की आय भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। बर्ड व्याख्या करते हैं कि भारत की तुलना में अन्य देशों में सुधार तेज़ी से क्यों हुए। सभी देशों में निहित स्वार्थ सुधारों के रास्ते में आड़े आते हैं। हालांकि, उन देशों के नेताओं ने किसान-मज़दूरों के अधिकारों का समर्थन किया, न कि पूंजीपति-मालिकों का। सुधारों से छोटे किसानों की कमाई और संपत्ति बढ़ी, और उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा में ज़्यादा निवेश किया। गौरतलब है कि लोगों को खेती से हटाए बिना भी, कृषि-उत्पादन और कृषि उत्पादकता बढ़ी है।

अर्थशास्त्रियों और व्यापार करने वालों को उद्यमों में 'पैमाने' पर फिर से सोचना चाहिए। एक मानकीकृत वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन, चाहे यह फैक्टरी उत्पादन बढ़ाने में सहायक कोई प्रक्रिया हो या बड़े खेत में एक ही फसल उगाना, बड़ी मशीनों का उपयोग और दोहराव वाले कामों को करने के लिए कम कुशल श्रमिकों को रोज़गार देकर अपनी आर्थिक दक्षता बढ़ाता है। बड़े पैमाने के उद्यमी मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूंजी लगाने की हैसियत रखते हैं। इस तरह, उन्हें कम श्रमिक और बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करके जहां उनकी दक्षता और उत्पादन मात्रा बढ़ सकती है, और उत्पादकता भी। ऐसे उद्यम कम श्रमिकों को नौकरी पर रखते हैं। वे अर्थव्यवस्था के 'रोजगार रहित' सकल घरेलू उत्पाद बढ़ोतरी से योगदान करते हैं।

छोटे खेत जो जैविक तरीके से उन्नत किस्म की फसलें उगाते हैं, उन खेतों में उत्पादन की 'संभावना' ज़्यादा होती है। कचरा खेत में अपने आप उपयोगी अवयव बन जाता है, खासकर उन खेतों में जहां पर जानवर भी रखे होते हैं। ज़्यादा संभावना वाले खेत स्वाभाविक रूप से अधिक टिकाऊ होते हैं। ऐसे छोटे खेतों में, जिनका पैमाना कम किंतु संभावना अधिक हो, सामग्री और ऊर्जा अपने भीतर और ऐसे छोटे खेतों के आसपास ही घूमती रहती है।

पर्यावरण वैज्ञानिक वैक्लाव स्मिल ने आधुनिक उद्योगों, खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणालियों, और वैश्विक परिवहन प्रणालियों में हाइड्रोकार्बन ऊर्जा और अन्य गैर-नवीकरणीय अवयवों की सकल व्यवस्थात्मक ज़रूरतों की गणना की है। अपनी किताब, हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क्स में, वह समझाते हैं कि आधुनिक एवं सघन तकनीकी विधि से बड़े पैमाने का खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणाली मिट्टी, पानी और वातावरण का सबसे बड़ा प्रदूषक है। वह यह भी समझाते हैं कि ज़्यादा संभावना वाले छोटे पैमाने के खेत पर्यावरणीय स्थिरता के लिए सबसे उपयुक्त वैज्ञानिक उपाय हैं।

वह बताते हैं कि समस्या यह है कि इस किस्म के समाधान में ज़्यादा लोगों को ग्रामीण इलाकों में बने रहने और काम करने, और छोटे कृषि, विनिर्माण और सेवा उद्यमों में शामिल होने की ज़रूरत होगी। इसके लिए चक्र उल्टा घुमाकर लोगों को शहरी, औपचारिक उद्यमों से निकालकर ग्रामीण, अनौपचारिक उद्यमों की ओर ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। विकसित देशों के नागरिक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। भारत को अन्य देशों जितनी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पहले से ही सबसे ज़्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में है और काम करती हैं।

सकल घरेलू उत्पाद की उच्चतर बढ़ोतरी से भारत के एक अरब से अधिक नागरिकों की भलाई-स्तर में सुधार नहीं होगा। पिछले 25 सालों से, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अन्य बड़े देशों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की प्रत्येक इकाई में वृद्धि होने के बावजूद कम रोज़गार पैदा किया है। हमारे पास दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है, जो अच्छी कमाई वाले रोजगार की तलाश में हैं।

अरूण मेरा

विकास के मौजूदा ढर्रे के साथ, पर्याप्त रोज़गार पैदा करने के वास्ते अगले कुछ सालों तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 12 प्रतिशत सालाना होनी चाहिए। जीडीपी वृद्धि की प्रत्येक इकाई अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट का कारण भी बन रही है। इसलिए, भारत उस शहरी-औद्योगीकरण विकास मॉडल का पालन जारी रखना गवारा नहीं कर सकता, जिसने वैश्विक पर्यावरण और असमानता संकट पैदा किए हैं।

हमारे देश को रहने लायक और टिकाऊ 'विकसित भारत' बनने के लिए विकास का नमूना बदलना होगा। जीडीपी पायदान पर अन्य देशों से ऊपर रहने का लक्ष्य रखने की बजाय, भारत के आर्थिक सुधारकों को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में ही सुधार करना चाहिए।

हमें अपना रास्ता खोजना होगा; एक अधिक समावेशी और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ रास्ता; अपने देश को बनाने और अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का एक अधिक 'पारिवारिक' एवं 'सामुदायिक' तरीका कृएक ज़्यादा 'गांधीवादी तरीका'कृ वह जो देश निर्माण करे और सभी नागरिकों को पूर्ण स्वराज (संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आज़ादी) दे सके।

कच्चे रास्ते पर जननी एक्सप्रेस ले जाने से ड्रायवर का इन्कार

लोडिंग वाहन के जरिए प्रसूता को एंबुलेंस तक पहुंचाया

माही की गूंज, रतलाम।

जिले की जावरा तहसील अंतर्गत ग्राम अर्जला में सोमवार रात एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने ग्रामीण सड़कों की हकीकत और आपातकालीन व्यवस्था की संवेदनहीनता दोनों को उजागर कर दिया। प्रसव पीड़ा से तड़प रही प्रसूता चालक की हठधर्मिता के कारण जननी एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी और स्वजनों को उसे लोडिंग वाहन में बैठाकर करीब 200 मीटर कच्चे रास्ते से शासकीय स्कूल के पास खड़ी एम्बुलेंस तक लाना पड़ा।

ग्राम अर्जला निवासी 23 वर्षीय ज्योति पत्नी भेरूलाल सूर्यवंशी को सोमवार शाम प्रसव पीड़ा शुरू हुई। शाम करीब 6:20 बजे आशा कार्यकर्ता ने 108 जननी एक्सप्रेस को सूचना दी। लगभग 15 मिनट में एम्बुलेंस (क्रमांक सीजी 04 एनवी 6402) गांव तो पहुंच गई, लेकिन चालक ने कच्चा रास्ता बताते हुए वाहन घर तक ले जाने से मना कर दिया और स्कूल के समीप ही खड़ा कर दिया।

करीब एक घंटे तक मान मन्नोवल के बाद भी चालक नहीं माना। इसके बाद करीब 08 बजे बाद लोडिंग से ज्योति को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। ज्योति ने मंगलवार तड़के जावरा के सिविल अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया।

एक घंटे तक ग्रामीण भी करते रहे आग्रह

प्रसूता के पिता जुझारीलाल अजमेरिया ने बताया कि वे बेटी को प्रथम प्रसव के लिए दो माह पूर्व आलोट के लसुड़िया सूरजमल स्थित ससुराल से अर्जला लेकर आए थे। गांव की नई आबादी में उनके अलावा 25 से अधिक परिवार निवास करते हैं और इसी रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों दोपहिया-चारपहिया वाहन निकलते हैं। घर तक मात्र 200 मीटर कच्चा रास्ता है।

मौसम खराब था

जुझारीलाल ने बताया कि मौसम खराब था, चालक से बार-बार आग्रह किया कि प्रसूता की हालत गंभीर है, घर तक वाहन ले आएं। इस पर चालक ने कहा, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, आप खुद लेकर आओ, बाइक से ले आओ। जब कहा कि बाइक से कैसे ला सकते हैं, तब भी चालक नहीं माना। यहां तक कि उन्होंने ट्रैक्टर भेजकर एम्बुलेंस फंसने पर निकालने की बात कही, लेकिन चालक ने मना कर दिया और बोला कि ट्राली में बैठाकर ले आओ। वे घर पर अकेले पुरुष थे।

इस पर सरपंच प्रतिनिधि बालू बोडाना को सूचना दी गई। वे मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके कहने पर भी चालक नहीं माना। इस दौरान गांव के 20 से अधिक लोग एकत्रित हो चुके थे। गांव में लोकेंद्रसिंह चंद्रावत को उनकी जीप के लिए फोन किया गया, लेकिन वह उपलब्ध नहीं थी। मजबूरी में लोकेंद्रसिंह का लोडिंग वाहन बुलाया गया, जिसमें प्रसूता को बैठाकर स्कूल तक लाया गया। वहां से एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया।

वीडियो में ड्राइवर बोला- अधिकारियों ने मना किया

घटनाक्रम के दौरान बनाए गए वीडियो में चालक अपना नाम नवदीप पाठक बताते हुए कहता दिखाई दे रहा है कि अधिकारियों ने मना किया है। एम्बुलेंस कच्चे रास्ते पर ले जाने जैसी नहीं है। जब लोगों ने उससे कहा कि लोडिंग भी तो आई है, तो चालक ने जवाब में कहा कि रोड ठीक होता तो ले आता, एम्बुलेंस लोडिंग नहीं है। चालक के साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति भी वीडियो में ग्रामीणों को रोड ठीक करवाने की नसीहत देते सुनाई दे रहा है।

खराब सड़क पर जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं ध्यान

जुझारीलाल का कहना है कि इस मार्ग की खराब स्थिति के बारे में कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक सड़क निर्माण नहीं हुआ। जुझारीलाल ने पूरे घटनाक्रम की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी दर्ज कराई है, ताकि भविष्य में किसी अन्य प्रसूता या मरीज को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

ड्राइवर और एजेंसी पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजेंगे

मामले में आशीष चौरसिया, जिला नोडल अधिकारी जननी एक्सप्रेस का कहना है कि, भोपाल से प्राइवेट एजेंसी द्वारा जननी एम्बुलेंस का संचालन किया जाता है। चालक व एजेंसी पर कार्रवाई के लिए मामले की जांच कर रिपोर्ट बनाकर भोपाल में प्रेषित करेंगे।

खाना खाते समय युवक गले में फंसी हड्डी

माही की गूंज, शाजापुर।

जरा सी लापरवाही कभी-कभी जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसा ही एक मामला शाजापुर जिला अस्पताल में सामने आया, जहां चिकन खाते समय 24 वर्षीय युवक के गले में हड्डी फंस गई और उसकी सांस अटकने लगी। समय रहते इलाज मिलने से युवक की जान बच सकी।

कन्हैयालाल रात अपने घर पर भोजन कर रहे थे। इसी दौरान चिकन की एक नुकीली हड्डी अचानक उनके गले में अटक गई। देखते ही देखते उनकी हालत बिगड़ने लगी। न तो वे ठीक से बोल पा रहे थे और न ही कुछ निगल पा रहे थे। सांस लेने में भी भारी दिक्कत होने लगी, जिससे घरवाले घबरा गए।

परिजनों ने बिना समय गंवाए कन्हैयालाल को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में मौजूद डाक्टरों ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। जांच में स्पष्ट हुआ कि हड्डी गले के अंदर खतरनाक स्थिति में फंसी हुई है।

डॉक्टर की तत्परता से टली अनहोनी

ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर तेजपाल सिंह जादौन ने तुरंत सर्जरी का निर्णय लिया। पूरी सावधानी और कुशलता के साथ गले में फंसी हड्डी को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। ऑपरेशन के बाद युवक की सांस सामान्य हुई और उसकी हालत में तेजी से सुधार आया। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है और डॉक्टरों की निगरानी में है।

कन्हैयालाल के परिजनों का कहना है कि यदि थोड़ी भी देर हो जाती, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। डॉक्टर तेजपाल सिंह जादौन ने लोगों से अपील की है कि भोजन करते समय जल्दबाजी न करें और हड्डी वाले खाद्य पदार्थ खाते समय विशेष सावधानी बरतें। साथ ही यदि गले में कुछ फंस जाए, सांस लेने में परेशानी हो या निगलने में दिक्कत हो, तो घरेलू उपायों में समय न गंवाकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें।

जो लड़का-लड़की भागकर लव मैरिज करेंगे...

माही की गूंज, रतलाम।

जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जो भी लड़का या लड़की भागकर शादी करेगा, उसे उसके परिवार वाले निकाल देंगे।

वीडियो में यह भी कहा गया है कि दूधवाले और नाई भी उनके घर नहीं आएंगे। उनसे जुड़े परिवारों को भी निकाल दिया जाएगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें लोगों ने पंचायत के तालिबान जैसे आदेश की कड़ी आलोचना की है।

यह घटना रतलाम जिले के पंचेवा गांव में हुई। पंचायत ने लव मैरिज करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस ऐलान का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें लव मैरिज करने वाले युवक-युवती और उनके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। वीडियो में दूध की सप्लाई रोकने, मजदूरी न देने और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखने जैसी सजाओं का ऐलान किया गया है।

गांव के तीन परिवारों को निकाल दिया जाएगा

वीडियो का विज्ञापन करने वाले व्यक्ति का यह भी कहना है कि लव मैरिज करने वालों की जमीन कोई किराए पर नहीं देगा। कोई पुजारी या नाई उनके घर नहीं जाएगा। कोई भी उनके घर किसी और काम के लिए नहीं जाएगा। जो लोग लव मैरिज करने वाले बाहरी लोगों को पनाह देंगे, उन्हें भी समाज से निकाल दिया जाएगा। वीडियो के आखिर में तीन गांववालों के नाम बताए गए हैं जिन्होंने लव मैरिज की है और उन्हें निकाल दिया गया है। वीडियो में उनका साथ देने वालों का भी बॉयकॉट करने की बात कही गई है।

हर खेत पर जाकर किया जाएगा सर्वे- उप मुख्यमंत्री

माही की गूंज, मंदसौर।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर जिले में ओलावृष्टि एवं वर्षा से प्रभावित फसलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम कितुखेड़ी, गोपालपुर, लोढ़ाखेड़ा, झारड़ा, अड़मालिया, किशनगढ़ में किसानों के खेतों में पहुंचकर अफीम, गेहूं, चना, चिया, अलसी सहित अन्य फसलों को देखा। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान किसी भी प्रकार की चिंता न करें। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में हर खेत पर जाकर सर्वे किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर गए हैं। सर्वे कार्य लगातार जारी है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, अधिकारी खेतों तक पहुंचकर वास्तविक स्थिति का आकलन कर रहे हैं। अफीम फसल के संबंध में नारकोटिक्स विभाग भी मौके पर जाकर खेतों का निरीक्षण कर रहे है। अफीम फसल को हुए नुकसान के विषय में केंद्र सरकार से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फसल बीमा के मामलों में भी किसानों को पूरा फसल बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में सरकार किसानों की हर चिंता और दुख में उनके साथ है। निरीक्षण के अवसर पर जिला योजना समिति सदस्य राजेश दीक्षित, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, मल्हारगढ़ एसडीएम सहित अन्य अधिकारी, बड़ी संख्या में किसान एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अफीम उत्पादक किसानों को बगैर सर्वे के मुआवजा देने की मांग

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र के किशनगढ़, झारड़ा, हरमाला, लसुडिया कदमाला, बोरखेड़ी, फतेपुर, बंड पिपलिया, पामाखेडा, गोपालपुरा, मनासाखुर्द, अनूपपूरा सहित अन्य गांवों में शनिवार को ओलावृष्टि व तेज बारिश से अफीम की फसल पूरी तरह चौपट होगई है।

किसानों को बगैर सर्वे के राहत एवं मुआवजे की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव परशुराम सिसौदिया की अगुवाई में जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्रसिंह गुर्जर एवं मन्दसौर विधायक विपिन जैन की उपस्थिति में मन्दसौर नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव व नारेबाजी कर केंद्रीय वित्तमंत्री एवं जिला अफीम अधिकारी के नाम जिला अफीम अधिकारी एस के हिंगड़ को मंगलवार को ज्ञापन सौंपे।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्रसिंह गुर्जर ने कहा कि, मल्हारगढ़ क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से अफीम की फसल पूरी तरह तबाह हो गई है अफीम के डोडे सहित पत्ते टूट गए है और अफीम में 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने केन्द्रीय वित्तमंत्री सीतारमण से किसान हित में मांग की है कि अफीम उत्पादक किसानों को राहत प्रदान की जाय।

इस मौके पर पुर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, प्रकाश रातड़िया, सोमिल नाहटा, मनजीत सिंह टूटेजा, अनिल शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस ने एवं क्षेत्र के किसान मौजूद थे।

महिला और किशोरी से छेड़छाड़, सात आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, उज्जैन।

ट्रेन में सवार मुस्लिम समाज के कुछ स्थानीय युवकों ने एक महिला यात्री व एक किशोरी के साथ अभद्रता व छेड़छाड़ की। शिकायत पर राजकीय रेलवे पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर पाक्सो एक्ट भी लगाया गया है। गिरफ्तारी की सूचना के बाद शहर में हंगामा होने लगा। बवाल बढ़ता देख भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया।

पुलिस के अनुसार रविवार को दाहोद (गुजरात) से चार महिलाएं और पुरुष उज्जैन में अस्थि विसर्जन के लिए आ रहे थे, रतलाम से खाचरौद के बीच मुस्लिम समुदाय के एक युवकों ने महिलाओं से अभद्रता व छेड़छाड़ की। साथ यात्रा कर रहे पुरुषों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की। यही नहीं अगले स्टेशन पर उनके कुछ और साथी भी ट्रेन में आ गए और मारपीट करने लगे।

ट्रेन के नागदा पहुंचने पर आरपीएफ के जवानों ने महिलाओं और उनके स्वजन को अपनी सुरक्षा में ले लिया। इस बीच नागदा रेलवे स्टेशन पर दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए। दोनों समुदाय के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आसपास के बाजार बंद हो गए। रविवार रात में दो घंटे तक स्टेशन परिसर में हंगामा चलता रहा।

फरियादी को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाने लगे तो विशेष वर्ग की भीड़ उनकी तरफ बढ़ी पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तब जाकर भीड़ वहां से हटी। पुलिस रात को मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च करती रही। जीआरपी पुलिस ने इस मामले में अब्दुल रहमान, अमन, मोहम्मद आपेष निवासी चंबल सागर कालोनी, शनी मल्लाह निवासी दुर्गापुरा नागदा, अमन खां निवासी खाचरौद, बुरहान खान निवासी खाचरौद, इरफान मंसूरी निवासी चंबल मार्ग कालोनी नागदा को गिरफ्तार किया है। इन सभी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

जादू-टोना के फेर में पिता-पुत्र की हत्या

माही की गूंज, रतलाम।

पांच वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के शिवगढ़ थाने के गाँव ठिकरिया में हुए बहुचर्चित मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिनमें आरोपीया तुलसीबाई पति राधेश्याम पलासिया (45) उसकी पुत्री माया पिता राधेश्याम पलासिया (24) जेठ के लड़के राहुल पिता ईश्वरलाल पलासिया (27) निवासी धराड़, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी, 342, 450, 323, 302 में 10,10 वर्ष व दोहरे- दोहरे आजीवन कारावास की सजा व 111000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

प्रकरण में पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि 20 फरवरी 2021 को थाना प्रभारी शिवगढ़ आर.एस. भाबोर द्वारा शिवगढ़ थाने पर रिपोट दर्ज करवाई गई की में आज दिनांक को कानून व्यवस्था इंतजाम कस्बा भ्रमण पर था इसी दौरान जिला चिकित्सालय रतलाम पुलिस चौकी से प्रधान आरक्षक अशोक शर्मा द्वारा मुझे जरिए मोबाईल फोन से सूचना दी गई की राजाराम पिता कांजी उर्फ कन्हैयालाल खराड़ी, उम्र 24 साल, निवासी गांव ठिकरिया को जादू टोना के दौरान मारपीट की है जिसे मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय रतलाम लाए है और ठिकरिया गांव में कांजी उर्फ कन्हैयालाल के घर पर जादू टोना करने वाले सभी लोगो को कमरे में बंद कर रखा है।

उक्त सूचना पर पुलिस ग्राम ठिकरिया घटनास्थल पहुंची, जहा भीड लगी हुई थी। अंदर किसी बड़ी घटना की आशका होने से मौके पर उपस्थित फोर्स व गवाहों की मदद से लकड़ी के दरवाजे को तोडकर कमरे के अदर प्रवेश किया। कमरे के अंदर तिखी सेंट की गंध आ रही थी एक छोटा बच्चा आर्दश उम्र करीब 3 साल के ऊपर माया नाम की लड़की बैठी हुई थी व उसके मुंह में अपनी उंगलियां फसा रखी थी और आर्दश अर्धमूर्छित अवस्था में था जिसके ऊपर से माया को तत्काल हटाया। कमरे में ही वृद्ध महिला थावरीबाई को भी जमीन पर गिराकर उसके ऊपर तुलसीबाई बैठी हुई थी।थावरीबाई घायल अवस्था में थी जिस पर से तुलसी को अलग हटाया। कमरे में अनिता पति विक्रम खराड़ी कोने में अपनी 06 वर्ष की बच्ची निकिता को लेकर बैठी थी जो काफी घबराई हुई थी निकिता को भी चोट लगी हुई थी। वहीं पर माला पति विजय खदेड़ा भी थी जिसकी कमर में चोट लग कर कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मौके पर घटना के संबंध में कन्हैयालाल उर्फ कांजी खराड़ी, अनिता पति विक्रम खराड़ी, विजय खदेड़ा व अन्य लोगो से पूछताछ की गई जिन्होंने बताया की मुसली, औंधी तलवार, स्टील की परात व लोटे से आरोपीगण के द्वारा मारपीट की है।

पुलिस ने सीबाई पलासिया, अजय पलासिया एवं माया पलासिया एवं अन्य तीन आरोपित के विरुद्ध जादू टोना तांत्रिक क्रियाओं के बहाने आपस में षडयंत्र रचकर राजाराम व उसके पुत्र आर्दश को जान से मारने की नियत से मारपीट कर हत्या करने व सीमाबाई, थावरीबाई व माला खदेड़ा को भी मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाने के अपराध में धारा 302, 307, 450, 120बी, 34 भादवि की एफआईआर दर्ज की गई।

जाँच के दौरान तुलसीबाई उसकी पुत्री माया उसके दोनों नाबालिक पुत्र पवन व अजय पलासिया तथा उसके जेठ के पुत्र राहुल उसके भाई विक्रम खराड़ी उसकी छोटी बहन सागर खराड़ी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर इनके विरुद्ध दिनांक 20.05.21 को चालान न्यायालय में पेश किया।

शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि न्यायालय में कुल 25 गवाहों के बयान करवाए व 85 दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा इसके साथ ही आरोपी माया से जप्त तलवार व लेगी तथा आरोपी राहुल से जप्त कपड़ों को जांच के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट में माया से जप्त तलवार व लेगी तथा राहुल के कपड़ों पर मृतक आदर्श का खून पाया गया।

जुर्माने की राशि मैसे 50 हजार रुपए मृतक आदर्श के दादा कन्हैयालाल को व 10-10 हजार रूपये आहत थावरीबाई, निकिता व माला को दिलाने का आदेश भी न्यायालय ने किया।

आरोपी तुलसीबाई, माया व राहुल गिरफ्तारी द 22/02/2021 से जेल में बंद है। आरोपित विक्रम पिता कन्हैयालाल खराड़ी, उम्र 33 साल व उसकी छोटी बहन सागर पिता कांजी उर्फ कन्हैयालाल खराड़ी, उम्र 27 साल निवासी ठिकरिया को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों को नुकसानी

एसडीएम ने नहीं उठाया फोन तो सोशल मीडिया पर फूटा मंडल अध्यक्ष का गुस्सा

शोशल मीडिया पर इस प्रकार की पोस्ट की झकनावद मंडल अध्यक्ष।

बेमौसम बारिश ओर ओलावृष्टि से इस प्रकार से हुआ गेहूं की फसल की नुकसान

माही की गूंज, पेटलावद।

स्थानीय अधिकारियों के रवैए खास कर पेटलावद पदस्थ होने के बाद से विवादों में रही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आईएएस तनुश्री मीना की कार्यशैली से न केवल आम जनता बल्कि अन्य विभागों के कर्मचारी और सत्तापक्षीय नेता तक कई बार नाराजगी दर्ज करवा चुके है। स्थानीय पत्रकार तो मैडम के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव तक पारित कर चुके है। लगातार विवादों में रहने के बाद कई बार उनकी शिकायत केबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी पहुंची। केबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने कई मौकों पर व्यवहार सुधारने के लिए फटकार तक लगाई लेकिन व्यवहार सुधारना तो ठीक केबिनेट मंत्री के पेटलावद विकासखंड के दौरे पर होने के समय कई मौकों पर उनके साथ दिखाई तक नहीं दी तो कई मौकों पर बीच दौरे में छोड़ कर अपने कार्यालय वापस लौट गई। कई गंभीर मुद्दों पर एसडीएम मीना ने मौके पर पहुंच कर मोर्चा तक नहीं संभाला , किसान आंदोलन भी बड़े स्तर तक पहुंचा जिसके पीछे एसडीएम मीना की कमजोरी सामने आई।

ओलावृष्टि से हुई नुकसानी ,मैडम ने नहीं उठाया फोन

लगातार विवादों में रही आईएएस एसडीएम तनु श्री मीना एक बार फिर चर्चा में हैं, मंगलवार को क्षेत्र में बिन मौसम बरसात हुई साथ ही तेज हवा ओर ओलावृष्टि के चलते गेहूं,चने सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा था। जानकारी के अनुसार झकनावद ओर रायपुरिया में ओलावृष्टि से किसानों को हुई नुकसानी की सूचना एसडीएम को मोबाइल द्वारा देने का प्रयास किया गया लेकिन मैडम ने फोन अटेंड नहीं किया , किसानो ने भाजपा के झकनावदा मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र राठौर को क्षेत्र में हुई फसल नुकसानी की जानकारी देकर आधिकारियों से संपर्क कर जानकारी देने को कहा, बताया जा रहा है की, इसके बाद क्षेत्र में हुई फसल नुकसानी की जानकारी के लिए झकनावद भाजपा मंडल अध्यक्ष ने एसडीएम को फोन किया मगर उनका भी फोन अटेंड नहीं हुआ। जिसके बाद नाराज मंडल अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक के बाद एक तीन पोस्ट कर डाली जिसमें एसडीएम को मुख्यमंत्री से भी बड़ी होना बताया। पोस्ट के बाद स्थानीय राजनीति में एक बार फिर एसडीएम चर्चा में आ गई ओर शिकायते केबिनेट मंत्री सहित प्रभारी मंत्री तक पहुंच गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र राठौर ने बताया कि क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुई नुकसानी की सूचना देने ओर नुकसानी का मौका मुआयना करने के लिए फोन लगाया लेकिन मैडम फोन तक नहीं उठाती और ऐसा पहला मौका नहीं है पूर्व में भी इस प्रकार का रवैया ही रहा है जो ठीक नहीं था। राठौर ने बताया कि जिला कलेक्टर नेहा मीना को सूचना देने के बाद राजस्व की टीम जांच करने पहुंची।

ओले गिरने से गेहूँ की फसल सहित सब्जियों को हुआ नुकसान

बैमौसम बारिश से एक ओर फसलों को नुकसान हो रहा है तो दुसरी और आमजन के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहा है। मौसम के परिवर्तन से फसलों पर प्रतिकुल प्रभाव पड रहा है। गेहूं और चने की फसल के साथ ही सब्जीयों और अन्य फसलों को नुकसान हो रहा है। क्षेत्र में कही हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश और तेज हवा तथा ओले गिरने से फसले खराब हो रही है। क्षेत्र के ग्राम पीठडी, बोलासा, कचरा खदान, जमुनिया, बरवेट सहित आसपास के किसानों के खेतों में गेहूं आडे हो गये है। जिसका कारण बारिश के साथ ओले गिरना और तेज हवा चलना है।

बैमौसम बारिश के कारण किसानों की फसले बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि यह पानी और इस प्रकार का मौसम फसलों के लिए अच्छा नहीं है। पीठडी के किसान देवीलाल कालूराम पाटीदार का कहना है कि मैने गेहूं लगाये थे। पिछले दो दिनों में मौसम परिवर्तन और गार गिरने से मेरी कई बीघा की गेहूं की फसल खराब हो गई है। मै सरकार से मांग करता हूँ की सर्वे करवा कर उचित मुआवजा दिया जाये।

नए भवन में पुरानी ईंटे, पुराने शौचायल पर ही भर दी छत

माही की गूंज, पेटलावद।

पुराने जर्जर शौचायल पर ही भर दी नई छत।

भवन के एक हिस्से में छत भरने से पहले ही प्लास्टर कर पुरानी ईटो से हुए निर्माण को छुपाने की कोशिश।

नगर के वार्ड क्रमांक 06 में वन विभाग द्वारा निर्माणाधीन भवन में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वन विभाग के जिम्मेदार नए भवन के निर्माण में की जा रही लापरवाही को अनदेखा कर रहे है। जानकारी होने के बाद भी किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया जिसके चलते भवन के निर्माण के नाम पर पुराने को नया दिखाने की कोशिश ओर विभाग की जानकारी में आने के बाद भ्रष्टचार को छुपाने की कोशिश की जा रही हैं। मामला वार्ड क्रमांक 06 का है जहां वन विभाग द्वारा नया भवन बनाया जा रहा है , विभाग द्वारा निर्माण में पहले तो जर्जर भवन से निकली घटिया ओर पुरानी ईटो का उपयोग भवन के एक हिस्से की दीवार में किया गया। मामला विभाग के अधिकारीयों के संज्ञान में आया तो कार्य करवा रहे विभाग के जिम्मेदार ने छत भरने से पहले ही पुरानी ईंटों से बनी दीवार जो बहार से खुली आंखों से देखी जा सकती है उस पर प्लास्टर कर छुपाने की कोशिश की है । साथ ही भवन की नींव में भराव के लिए भी जर्जर भवन के मटेरियल का उपयोग किया गया। ये सारी कारिस्तानी विभाग की जानकारी में होने के बाद कोई सुधार नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि भवन के साथ शौचालय का भी निर्माण किया जाना था, लेकिन मौके पर जाने पर पता लगा कि पुराने जर्जर शौचायल को ही नए सिरे से छत भर कर नया बताने का प्रयास हो रहा है। फिलहाल विभाग नगर के बीचों बीच आम जनता के सामने इस प्रकार से घटिया निर्माण कर रहा है तो जंगल (वन क्षेत्र) में होने वाले निर्माण कार्यों में क्या स्थिति होती होगी ये स्वतः ही पता चलता है।

अस्पताल में स्टीवर्ड पद से लाइनमैन को हटाया

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा जिला अस्पताल में नियम विरुद्ध नियुक्ति एवं विद्युत सामग्री खरीदी में अनियमितता को लेकर विवाद सामने आया है। निविदा फर्म की शिकायत के बाद अस्पताल में पदस्थ स्टीवर्ड को पद से हटा दिया गया है। मामला निविदा प्रक्रिया के बावजूद बाजार से सामग्री खरीदे जाने और लाइनमैन को अधिकारी स्तर का प्रभार दिए जाने से जुड़ा है।

जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल में कूलर, पंखे, फ्रिज और वातानुकूलन यंत्र जैसी विद्युत सामग्री की खरीदी के लिए निविदा प्रक्रिया के तहत प्रिंस इंटरप्राइजेज को अधिकृत किया गया था। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने निविदा फर्म के बजाय बाजार से सामग्री खरीद ली। फर्म का आरोप है कि इस संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। प्रिंस इंटरप्राइजेज ने खरीदी प्रक्रिया को लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सामग्री खरीदी और मरम्मत से संबंधित जानकारी मांगी। इसी बीच अस्पताल प्रशासन ने जिला अस्पताल में पदस्थ स्टीवर्ड अश्वनी लुक को पद से हटा दिया। फर्म का आरोप है कि अश्वनी लुक का मूल पद लाइनमैन का है, इसके बावजूद उन्हें अधिकारी स्तर के स्टीवर्ड पद का प्रभार दिया गया था, जो नियमों के विरुद्ध है। फर्म का कहना है कि निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अन्य माध्यम से खरीदी किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। 29 जनवरी को जारी आदेश में सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल ने अश्वनी लुक से स्टीवर्ड का प्रभार हटाते हुए मैनेजर यशवंत सोलंकी को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रिंस इंटरप्राइजेज का कहना है कि वह इस पूरे मामले को लोकायुक्त के समक्ष ले जाने की तैयारी कर रही है। फर्म के अनुसार, निविदा प्रक्रिया की अनदेखी कर अस्पताल प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर की गई खरीदी नियमों के विरुद्ध है। वहीं इस संबंध में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल ने बताया कि स्टीवर्ड अश्वनी लुक को लगातार बीमार रहने के कारण पद से हटाया गया है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस का विरोध

माही की गूंज, खरगोन।

कसरावद विधायक एवं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते के माध्यम से किसानों के हितों को अमेरिका के सामने गिरवी रखा गया है।प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सचिन यादव ने बुधवार दोपहर कसरावद में कहा कि देश के किसान पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकार द्वारा अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलना किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले का सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि वे विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं। भारतीय किसान पहले से ही बढ़ती लागत, मौसम की मार और बाजार की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में विदेशी कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना किसानों की आय बढ़ाने के सरकार के दावों के विपरीत है। सचिन यादव ने केंद्र सरकार से मांग की कि इस व्यापार समझौते में किसानों के हितों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसलों के उचित दाम और घरेलू कृषि बाजार की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस समझौते में किसानों के हितों की अनदेखी की, तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन करेगी।

सात मजदूरों के महाराष्ट्र में बंधक होने की आशंका

माही की गूंज, खंडवा।

आदिवासी विकासखंड खालवा से मजदूरी करने गए सात युवकों के महाराष्ट्र में बंधक बनाए जाने की आशंका सामने आई है। मामले को लेकर पीड़ित युवकों के परिजन खालवा थाने पहुंचे और पुलिस से उन्हें सुरक्षित मुक्त कराने की गुहार लगाई है।

देवलीखुर्द निवासी भैयालाल पिता मांगीलाल काजले ने बताया कि जनवरी माह में उनके बेटे राहुल और कोमल सहित गांव के अरुण पिता मोतीराम तथा विशन पटेल समेत कुल सात युवकों को राजस्थान निवासी आशिक नामक ठेकेदार ने प्रतिदिन 800 रुपए मजदूरी का लालच देकर थ्रेसर मशीन पर काम कराने के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर ले जाया था।

भैयालाल के अनुसार कुछ दिनों बाद ठेकेदार का मोबाइल बंद हो गया और युवकों के मोबाइल भी लगातार बंद आने लगे। शनिवार को उनके बेटे ने किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल से फोन कर बताया कि सभी युवकों को सोलापुर में बंधक बनाकर रखा गया है और उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए गए हैं। युवक ने पुलिस को सूचना देकर उन्हें छुड़ाने की गुहार लगाई।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन रविवार को खंडवा पहुंचे और मंत्री विजय शाह के निवास पर गए, जहां उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। परिजनों ने मंत्री के स्टाफ को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें खालवा थाने में शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

मंगलवार को ग्राम कोटवार आशाराम के साथ परिजन खालवा थाना पहुंचे। पुलिस ने युवकों के फोटो, आधार कार्ड, ठेकेदार का नाम एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने पर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खालवा थाने के उपनिरीक्षक भुवनसिंह वास्कले ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि युवक किसके साथ और कहां मजदूरी करने गए हैं। परिजनों से ठेकेदार की पूरी जानकारी और संपर्क नंबर लाने को कहा गया है, ताकि युवकों की तलाश कर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके।

सड़क हादसे में सबसे ज्यादा शिकार युवा, तेज गति में हुए हादसों में प्रथम हुआ एमपी

पुलिस, परिवहन विभाग नियम पालन करवाने में असफल

माही की गूंज, झाबुआ।

समस्या के समाधान पर सरकार सोचने में सुस्त है, क्योंकि जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत हादसों का देश बनता जा रहा है। और इन हादसों में मरने वालों से देश एक प्रकार की आपदा का परिचायी हो सकता है। यदि अभी भी सरकार, सड़क परिवहन या फिर यातायात के प्रति सजग नहीं होकर जनता को सजग नहीं किया तो यह देश, हादसो में मरने वालों का देश हो सकता है। चिंताजनक है कि, हादसों में मरने वालों की संख्या प्रतिवर्षानुसार बढ़ती जा रही है जो की देश के लिए एक आपदा का रुप ले रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट देश में चिंता का विषय है।

रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में सड़को की बदहाली और सड़क सुरक्षा व्यवस्था की बदइंतजामी खुलकर सामने आई है। हादसों में पहले नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर मध्यप्रदेश है, जहां लाखों हादसे नियमों के तोड़ने पर, और 60 प्रतिशत दुर्घटनाएं जिनमें मौके पर ही मौत, 20 प्रतिशत मौतें अस्पताल पहुंचते- पहुंचते ही हो जाती है। वहीं 20 प्रतिशत मौतें उपचार के दौरान हो जाती है।

रिपोर्ट के अनुसार देशभर में 2023 में 4,80,583 सड़क हादसे जिसमें 1,72,890 की मौत और 4,62,825 घायल। घायलो में 50 प्रतिशत से ज्यादा गंभीर घायल है। रिपोर्ट में तेज गति के कारण होने वाली दुर्घटना में मध्यप्रदेश अव्वल नंबर पर है। वहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने के कारण सबसे ज्यादा दुर्घटना मध्यप्रदेश में हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार लोगों ने नियम तोड़े तभी वे दुर्घटना के शिकार हुए।

मध्यप्रदेश में 108 एंबुलेंस सेवा कंपनी की रिपोर्ट जिसमें वर्ष 2025 के आंकड़े निकाले गए है। जो कि, जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक के है। जिसमें यह बताया गया है कि, प्रदेशभर में जो सवा लाख दुर्घटनाएं हुई है उसमें सबसे ज्यादा शिकार युवा वर्ग हुआ है। इन दस माह में सड़क दुर्घटनाओं के मामले दर्ज किए गए है वो 1,23,863 है। प्रदेश की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा हादसो की शिकार हुई है। डेटा के अनुसार दुर्घटनाओं में 61 प्रतिशत अर्थात 75,661 मामले 15वर्ष से 30 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के है। तेज गति, ट्रैफिक नियमो की अनदेखी, और लापरवाही युवाओं पर भारी पड़ रही है। सड़क सुरक्षा, परिवहन जागरुकता, की आवश्यकता युवा वर्ग को बहुत ज्यादा है। दुर्घटनाओं के मामले में प्रदेश के बड़े शहर लंबे समय से हॉटस्पॉट बने हुए है, और अब छोटे शहर यहां तक गांव भी दुर्घटनाओं के मामले में लाईल लाईट हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इंदौर और भोपाल दुर्घटना की दृष्टि से प्रथम है। परंतु इस बार के आंकड़ों में सागर हादसो में प्रथम रहा है जहां दस माह में 6704 दुर्घटनाएं हुई है।

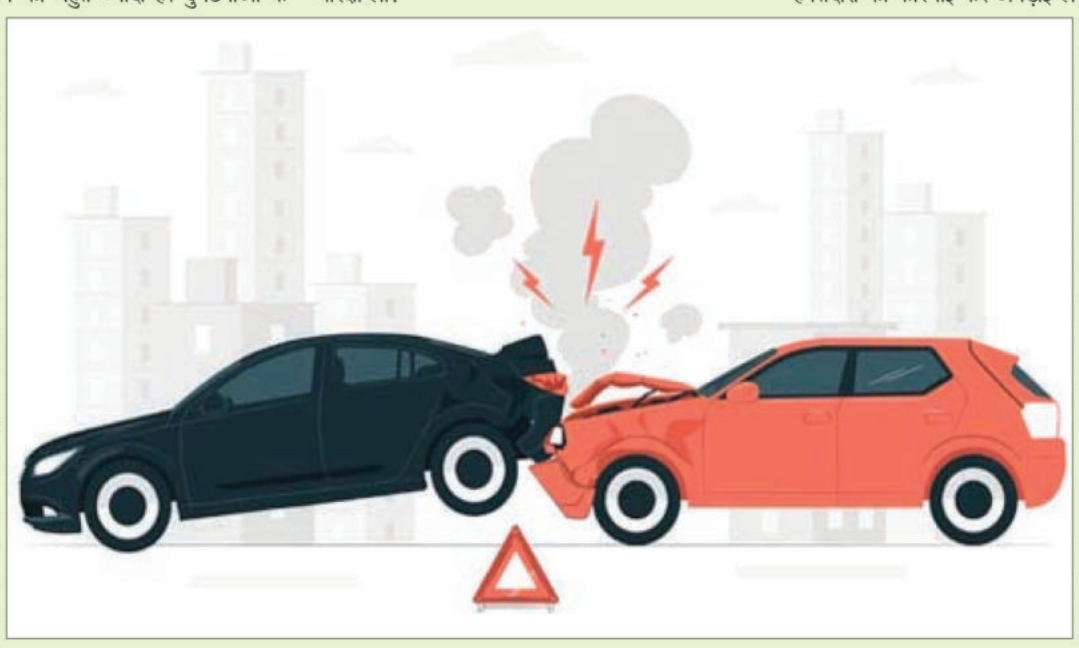

लोग नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं, क्या इस विषय पर कभी कोई गंभीर स्तर की चर्चा की गई? जिसकी रिपोर्ट पेश की गई हो। इस विषय पर क्या कभी सामाजिक स्तर पर कोई पहल की गई हो? इस विषय पर क्या कभी राजनीतिक विचार धारा के प्रभावी लोगों द्वारा मंच से लोगों को समझाईश दी गई? पुलिस द्वारा यातायात सप्ताह मनाने के अलावा दुर्घटना या हादसों को रोकने के कोई उपाय किए? परिवहन विभाग द्वारा लाईसेंस जारी करते समय वाहन चालक का परिक्षण या उसके नियमों की जानकारी की कोई परिक्षा ली?

इन सभी प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर एक शब्द में दिया जा सकता है। नहीं।

जब भी यातायात विभाग पर कोई दबाव आता है तो पुलिस, चौराहे पर खड़ी होकर लोगों को हेलमेट पहनाती है या न पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई करती है। तेज गति से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने में किसी को आगे आते नहीं देखा। परिवहन विभाग भी अपनी सुस्ती में मस्त हफ्तेदारी की कार्रवाई कर अंगड़ाई लेकर सो जाता है। तेज गति से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई आवश्यक है साथ ही समझाईश की भी जरुरत है।

सरकार, सड़क हादसों की समस्या को गंभीरता से नहीं लेगी तो यह परेशानी बढ़ती ही चली जाएगी। जनसंख्या वृद्धी होती जा रही है लोग बढ़ रहे हैं, शाम को सभी लोगों को ऑफिस से घर जाने की जल्दी होती है और उसी जल्दी में तेज गति से चलकर वो नियम तोड़ते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं।

रिपोर्ट में दर्शाए गए समस्त कारणों की गहराई में जाए तो ज्ञात होगा कि, व्यक्ति यातायात के सम्बंध में जागरुक नहीं है। उसे अपने अहंकार और अपनी मर्जी का काम करने में ज्यादा संतुष्टी मिलती है और इस संतुष्टी को वह वाहन चलाते समय भी पाना चाहता है जो की नियमानुसार सही नहीं है। यदि किसी बाइक वाले से कोई आगे निकल जाता है तो वह भी गति तेज कर उसका पीछा करके उसे पीछे करने की कोशिश करता है और कभी-कभी इसी कोशिश में वह दुनिया को पीछे छोड़ कर चला जाता है।

रिंकेश बैरागी

हालांकि, पुलिस वर्षभर में सात दिवस का यातायात सप्ताह मनाती है जिसमें वह अधिकतर विद्यालयो में जा-जा कर विद्यार्थियों को यातायात के सम्बंध में जागरुक करती है यह एक प्रकार से अच्छी बात है मगर क्या इन सात दिनों में इतनी जागरुकता आ जाती है कि, लोगों में यातायात की समझ आ जाए। अगर ऐसा होता तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट दुर्घटना के इतने भयानक आंकड़ो को प्रस्तुत नहीं करती न ही हादसों की विस्तृत जानकारी देकर हो चुके हादसों का विश्लेषण नहीं करती।

बहरहाल, हादसों को रोकने के लिए समझाईश की टोली को सक्रिय होकर वाहन चालको को यातायात के नियमों के बारे में बताना होगा। परिवहन विभाग के सहयोग से समाजिक संगठनों को सामने आ कर एक मुहिम के रुप में कार्यक्रमों को आयोजित करना होगा जिसमें समाज के सभी वर्गो की उपस्थिति को अनिवार्य करना होगा। तब कहीं यातायात के सम्बंध में जागरुकता फैलेगी और संभवतः सड़कों पर होने वाले हादसों में कुछ कमी होगी। वहीं सरकार को यातायात प्रबंधन और परिवहन के नियमों को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा जिससे भावी पीढ़ी पहले ही इस आपदा से सतर्क हो जाए और भारत देश में हाने वाले हादसे कम हो और युवा सड़को पर सुरक्षित रहे।

फतेह स्पोर्ट्स क्लब में पटेल ट्रॉफी सीजन 5 का हुआ भव्य समापन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

फतेह स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित पटेल ट्रॉफी सीजन 5 (2026) का भव्य समापन हुआ, जिसमें हजारों खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फाइनल मुकाबला जयस 11 और भाविन भरूच (गुजरात) की टीम के बीच खेला गया, जिसने दर्शकों को रोमांच और खेल भावना का अद्भुत अनुभव दिया।

जयस 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में 54 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। जवाब में भाविन भरूच (गुजरात) की टीम ने शानदार बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य हासिल कर फाइनल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पूरे मैच के दौरान दर्शकों की उत्सुकता चरम पर रही। मैदान में की गई भव्य आतिशबाजी, लाइव प्रसारण के माध्यम से पूरे जिले के खेल प्रेमियों तक उत्सव का अनुभव पहुँचाना और मशीनों से फूलों की पंखुड़ियों की बारिश ने माहौल को पूरी तरह से उत्सवमय बना दिया।

यह आयोजन लगातार पाँच वर्षों से पटेल ग्रुप द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की सफलता के पीछे युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पराज रावत पटेल, दिलीप पटेल, अमित घोटू, वासिम भाई सहित पूरी टीम की मेहनत और समर्पण है।

फाइनल मुकाबले के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। विजेता टीम भाविन भरूच को ?1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये) नकद और ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि उपविजेता जयस 11 को ?71,000 (इकहत्तर हजार रुपये) नकद और ट्रॉफी प्रदान की गई।

इस अवसर पर खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए भी कई प्रोत्साहन पुरस्कारों की बारिश हुई। बेहतरीन बल्लेबाजी, उत्कृष्ट गेंदबाजी, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज सहित कई पुरस्कार वितरित किए गए, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह और आत्मविश्वास और बढ़ गया।

महेश पटेल ने समारोह में उपस्थित खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पटेल ट्रॉफी हमेशा की तरह भविष्य में और भी भव्य रूप से आयोजित की जाएगी। उन्होंने सीजन 6 की घोषणा करते हुए बताया कि आगामी सीजन में अलग-अलग राज्यों से टीमें भाग लेंगी और इनामी राशि ?2,11,000 (दो लाख ग्यारह हजार रुपये) होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले सीजन में जिले की बेटियों के लिए महिला टीम बनाई जाएगी, ताकि वे खेलों में अपनी प्रतिभा से जिले का नाम रोशन करें और समाज में मिसाल कायम करें।

दर्शक दीर्घा में हजारों खेल प्रेमियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम का संचालन नगरपालिका उपाध्यक्ष सब्बीर बाबा ने किया। इस अवसर पर साहनी मकरानी, राजेंद्र टवाली सुरेश सारड़ा सहित अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे।

पटेल ट्रॉफी सीजन 5 ने यह साबित कर दिया कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और युवाओं में भाईचारा, ऊर्जा और खेल भावना को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। इस आयोजन ने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया और दर्शकों को यादगार पल दिए, जो आने वाले वर्षों तक याद किए जाएंगे।

केंद्रीय बजट लॉलीपॉप समान मध्यम वर्गीय किसान बेरोजगार उपेक्षित

माही की गूंज, अलीराजपुर।

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया बजट जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहा है यह बजट सिर्फ दिखावटी घोषणाओं तक सीमित है देश प्रदेश के मध्यम वर्गीय व निचले तबके की जनता के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

यह आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता साबिर फिटवेल ने बजट प्रस्तुत होने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर बताया कि यह बजट जनता को राहत देने के बजाय लॉलीपॉप साबित हुआ है। महंगाई बेरोजगारी ओर किसानो की समस्याओं से जूझ रही जनता और ग्रामीण क्षेत्र के किसान को इस बजट से उम्मीद थी कि हमारे हितार्थ केंद्र सरकार राहत प्रदान करेगी उसके विपरीत सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

साबिर फिटवेल ने कहा कि, मध्य प्रदेश के साथ भी एक बार फिर सौतेला व्यवहार हुआ है राज्य के लिए कोई विशेष पैकेज व विकास की ठोस योजना शामिल नहीं है। यह बजट पूंजी पतियों को लाभ पहुंचाने उन्हें राहत देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जबकि मध्यम वर्गीय व निचले स्तर की जनता युवा बेरोजगार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। 3 लाख युवाओ बेरोजगारों को बजट में नौकरी देने की बात तो कही है पर किस सेक्टर में और कब दी जाएगी यह उल्लेख नहीं किया यह सरासर धोखा है जो बिना रोडमेंप के जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए भी यह बजट में कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई किसानों को फसलों पर उचित मूल्य के दाम न कर्ज राहत ओर ना ही कृषि के दाम घटाने को लेकर प्रभावी घोषणा की है कांग्रेस पार्टी इस जन विरोधी किसान विरोधी बजट का विरोध करती है।

पांच माह से अतिथियों को नहीं मिला वेतन

माही की गूंज, बरझर। फिरोज खान

अतिथि शिक्षकों को पांच वाह से मानदेय नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब से स्कूल प्रारंभ हुई तब से लेकर आज तक अतिथि शिक्षकों का मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अपने परिवार का भरण पोषण करने में काफी तकलीफो का सामना करना पड़ रहा है । ऐसे में सरकार भी कम मानदेय पर छात्र-छात्राओं को पढ़ाने वाले का काम करने वाले अतिथि शिक्षक को मानदेय देने पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सम्बन्धत जिला अधिकारी से लेकर ब्लाक अधिकारियों के पास पांच माह का मानदेय नहीं मिलने को लेकर पहुंचे जिला अध्यक्ष भीका गणावा, जिला मिडिया प्रभारी हितेश कुमार अलावा ब्लाक अध्यक्ष अल्केश सोलंकी व ब्लाक उपाध्यक्ष राकेश जमरा को सन्तुष्ट जवाब भी नहीं मिल? रहा है। बस आगे से फंड नहीं आया एक ही जवाब मिलता है। ऐसे भी अतिथि शिक्षकों का मानदेय में देरी होने से दिन प्रतिदिन परेशान परेशानियों का सामना करने पर विवश होना पड़ रहा है। ज़िला अध्यक्ष मीका गणावा का कहना है कि, यदी समय रहते मानदेय नही मिला तो आने वाले समय में संगठन बढ़ा क़दम उठाने को मजबूत होना पड़ेगा।

जैन समाज भी सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा

माही की गूंज, धार।

प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मोहनखेड़ा में सोमवार को एक दिवसीय धार्मिक कथा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के प्रमुख कथावाचक पं. धीरेंद्र शास्त्री ने प्रवचन दिए। शास्त्री को सुनने के लिए हजारों श्रद्धालु मोहनखेड़ा पहुंचे। यह उनका क्षेत्र में पहला प्रवास था। प्रवचन के दौरान पं. धीरेंद्र शास्त्री ने मोहनखेड़ा की धरती को तीर्थ समान बताते हुए कहा कि यहां आदिनाथ भगवान और ऋषभदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सनातनी परंपरा का व्यापक आगाज हो रहा है। उन्होंने 15 फरवरी को बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले कन्या विवाह सम्मेलन का निमंत्रण भी श्रद्धालुओं को दिया। मीडिया से चर्चा में पं. शास्त्री ने कहा कि देश में सनातनी समाज को आपसी तनातनी से बचना चाहिए। संत और सनातनी समाज को एकजुट होकर धर्म की रक्षा करनी होगी।

जैन समाज भी सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा

उन्होंने कहा कि हिंदू और जैन एक हैं तथा जैन समाज भी सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। पं. शास्त्री ने धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में इनकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने सनातन समाज को जागरूक और संगठित रहने का आह्वान किया। एक दिवसीय कथा आयोजन को लेकर प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम के समापन पर देर शाम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अनुराधा पोडवाल ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। करीब एक घंटे तक चले प्रवचनों में धर्म रक्षा, सनातन समाज की एकजुटता और सामाजिक जागरूकता पर मार्गदर्शन किया गया।

मप्र में सनातन परंपरा का जागरण

शास्त्री ने कहा कि मप्र में सनातन परंपरा का व्यापक जागरण हो चुका है, जो समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहा है। पंडित कमल किशोर नागर द्वारा क्षेत्र के गांव-गांव में गोशाला निर्माण और मोहनखेड़ा क्षेत्र में हो रही गोसेवा की निष्ठा एवं कार्यों की सराहना की। शास्त्री ने समाज से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि आपसी एकता ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आगामी 15 फरवरी को बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले कन्या विवाह कार्यक्रम का आमंत्रण भी दिया।

महिलाओं के साथ पुरुषों की उमड़ी भीड़

कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। खुली जीप में बागेश्वर सरकार ने श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। कथा स्थल पर आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रवचन के दौरान मंच पर अयोध्या से आए कई संत और विभिन्न देव स्थानों के साधु संत और विधायक प्रताप ग्रेवाल मौजूद रहे।

धूम धाम से मनाई संत शिरोमणि श्री रविदास जी 649 वीं जयंती

माही की गूंज, आम्बुआ।

रैदास समाज के ही नहीं अपितु सर्व हिंदू सनातन धर्मावलंबियों में पूज्यनीय गुरु संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जयंती प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी आम्बुआ में उनके अनुयायियों द्वारा धूम धाम से मनाये जाने के समाचार है। इस अवसर पर समाज जनों ने एक झांकी निकाली गई, जिसका मार्ग में स्थान स्थान पर भव्य स्वागत किया गया। शोभायात्रा में विभिन्न समाज जन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आदि सम्मिलित हुए। झांकी पुनः हरिजन आवास फलिया पहुंची जहां पर संत श्री रविदास की तस्वीर की पूजा अर्चना कर आरती की जाकर कार्यक्रम का समापन हुआ। पुलिस की माकूल व्यवस्था रही।

ग्रामीणों को मिली बड़ी विकास सौगात

माही की गूंज, आलीराजपुर।

क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान द्वारा दो प्रमुख ग्रामीण सड़कों का विधिवत भूमिपूजन किया गया। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण अंचलों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलने के साथ-साथ विकास की नई राह खुलेगी।

कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान का अपनी जिले को विकसित एवं ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना मूर्तरूप लेते जा रहा। इसी कड़ी में उन्होंने 2 प्रमुख सड़को का भूमिपूजन किया। प्रथम सड़क कार्य अंतर्गत ग्राम तीती मिडिल स्कूल से ग्राम भाणारावत एवं कुडली होते हुए ग्राम खारकुआँ सेमली तक कुल 11.85 किलोमीटर लंबाई के मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क की अनुमानित लागत 14 करोड़ 39 लाख 53 हजार रुपये है। यह मार्ग क्षेत्र के कई ग्रामों को आपस में जोड़ते हुए मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वहीं दूसरा सड़क निर्माण कार्य ग्राम आम्बी से ग्राम रोशिया तक कुल 3.90 किलोमीटर लंबाई का है, जिसकी अनुमानित लागत 5 करोड़ 62 लाख 91 हजार रुपये निर्धारित की गई है। यह सड़क स्थानीय आवागमन को सुगम बनाने के साथ-साथ ग्रामीणों के दैनिक जीवन में सुविधा प्रदान करेगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नागरसिंह जी चौहान ने कहा कि, प्रदेश की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इन सड़कों का निर्माण केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का माध्यम भी है। सरकार का उद्देश्य है कि अंतिम छोर तक विकास पहुंचे और हर गांव शहरों से मजबूती से जुड़े। सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को अपना अनाज बाजार तक लेजाने सहित, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। क्षेत्रवासियों ने सड़क निर्माण कार्यों के लिए कैबिनेट मंत्री श्री नागरसिंह चौहान एवं प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

भूमिपूजन कार्यक्रम में सोंडवा जनपद उपाध्यक्ष विक्रम भयड़िया, मंडल अध्यक्ष गोविंद आवासीय, नानसिंह रावत, नारिन मोरी, मांगीलाल रावत, सरपाल अजनार, सहित कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

विधायक ट्राफी का फाइनल ऐतिहासिक रहा

अंतिम गेंद पर भी नहीं हुआ निर्णय, टाई हुआ मुकाबला

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद में खेल प्रेमियों की भारी उपस्थिति और खिलाड़ियों के जोश के बीच आयोजित पाँच दिवसीय विधायक कप टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार को भव्य, गरिमामय और ऐतिहासिक समापन हुआ। यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं के उत्साह, खेल भावना और सामूहिक प्रयास का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया।

टूर्नामेंट के शुभारंभ से लेकर अंतिम मुकाबले तक मैदान पर रोमांच, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। हर दिन दर्शकों की संख्या बढ़ती गई और अंतिम दिन तो मैदान पूरी तरह खेल प्रेमियों से खचाखच भर गया।

सेमीफाइनल मुकाबलों में दिखा रोमांच

टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला मिक्स 11 और यूके स्पोर्ट्स के बीच खेला गया। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन निर्णायक क्षणों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए यूके स्पोर्ट्स ने जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया।

इसके पश्चात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भूमा 11 रायपुरिया और आदिवासी क्रिकेट क्लब थांदला आमने-सामने रहे। यह मुकाबला भी दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा, जिसमें शानदार बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी के दम पर भूमा 11 रायपुरिया ने जीत हासिल कर फाइनल में अपनी जगह पक्की की।

फाइनल मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार

फाइनल मुकाबला यूके स्पोर्ट्स और भूमा 11 रायपुरिया के बीच खेला गया, जिसने पेटलावद के क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। भूमा 11 के गेंदबाजों ने सशक्त और अनुशासित गेंदबाजी करते हुए यूके स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती दी। हालांकि वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके, लेकिन मैच को टाई कराने में सफल रहे। दूसरी ओर यूके स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने भी शानदार खेल दिखाया और अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन बनाकर मुकाबले को टाई कर दिया। अंधेरा हो जाने के कारण आगे का खेल संभव नहीं हो सका, जिसके चलते आयोजकों द्वारा दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। यह पेटलावद के इतिहास में पहली बार हुआ, जब किसी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला टाई होने पर दोनों टीमों को विजेता घोषित किया गया। फाइनल मुकाबला टाई रहने के बाद भूमा 11 रायपुरिया एवं यूके स्पोर्ट्स टीम को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। इस अवसर पर प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार की कुल राशि को दोनों टीमों में समान रूप से विभाजित कर प्रदान किया गया। इस ऐतिहासिक निर्णय का दर्शकों ने तालियों की गूंज के साथ स्वागत किया।

कामेंट्री और अंपायरिंग रही सराहनीय

पूरे टूर्नामेंट के दौरान कामेंटेटर भरत चौधरी, अनिल लववंशी, यश रामावत एवं राकेश गेहलोत ने अपनी सजीव और रोचक कामेंट्री से मैच को और भी रोमांचक बनाया। वहीं अंपायर सचिन गामड़ और मनोज परमार ने निष्पक्ष एवं सटीक निर्णय लेते हुए ÷फेयर डिसीजन, फेयर अंपायरिंग÷ की मिसाल पेश की।

आयोजन समिति की मेहनत लाई रंग

15 दिनों की निरंतर मेहनत और समर्पण के साथ आयोजित इस सफल टूर्नामेंट के लिए आयोजन समिति प्रशंसा की पात्र रही। समिति की ओर से अप्पू भंडारी, जगदीश पाटीदार, नाना काग, विनोद चौधरी, मनोज परमार, प्रदीप राठौड़, कुलदीप सिसोदिया एवं सलमान शेख ने सभी अतिथियों, खिलाड़ियों, सहयोगियों, मीडिया एवं खेल प्रेमियों का आभार व्यक्त किया।

पेट्रोलिंग अधिकारी पर जानलेवा हमला

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले में उन्हेल रोड स्थित ग्राम ओरखेड़ी में पानी का वॉल्व बंद करने को लेकर हुए विवाद में नर्मदा लाइन की पेट्रोलिंग अधिकारी के साथ खेत मालिक और उसके साथियों ने सोमवार-मंगलवार की दरमियान रात मारपीट कर दी। जिससे अधिकारी घायल हो गया। पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

भैरवगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि, ग्राम पान बड़ोदिया निवासी जितेन्द्र पिता जुझारसिंह राजपूत नर्मदा लाइन पॉवर लिंक कंपनी में पेट्रोलिंग अधिकारी के पद पर पदस्थ है। पुलिस के अनुसार जितेन्द्र रात में पेट्रोलिंग के दौरान बड़ोदिया काजी क्षेत्र में लाइन की जांच कर रहा था। इसी दौरान ओरखेड़ी के पास एक खेत में व्यर्थ पानी बहता दिखाई दिया। पानी की बर्बादी रोकने के लिए उसने संबंधित वॉल्व बंद कर दिया। जैसे ही खेत मालिक तूफान को वॉल्व बंद होने की जानकारी लगी तो वह अपने साथी अश्विन, माखन और अन्य परिजनों के साथ वॉल्व पाइंट पर पहुंचा और जितेन्द्र से विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और तुफान सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर जितेन्द्र के साथ मारपीट की।

गांव छोडक़र भागे आरोपीपुलिस ने बताया कि, घटना की जानकारी मिलते ही नर्मदा लाइन कंपनी के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायल जितेन्द्र को उपचार के लिए चरक अस्पताल में भर्ती करवाया। भैरवगढ़ थाना पुलिस ने घायल के साथी ईश्वरसिंह की शिकायत पर खेत मालिक तूफान, अश्विन, माखन सहित अन्य के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। ह्यपुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी गांव से भाग निकले है।

मामला : संत तेरेसा स्कूल के बच्चों द्वारा फेयरवेल पार्टी एवं वाहन जुलूस में स्कूल के अंदर से लेकर खेल मैदान तक खतरनाक स्टंट का

बच्चों की सफलता का श्रेय स्कूल का लेकिन गलती पर स्कूल झाड़ लेता है अपना पल्ला, ऐसा क्यों...?

किसी घटना के बाद उसे अमल नही करना और फिर घटना को अंजाम देना बड़ा अपराध

बैको लोडर मशीन के लोडर पर संत तेरेसा स्कूल का बेनर। साथ ही मशीन व कारो पर खेल मैदान पर खतरनाक स्टंट करते विद्यार्थी।

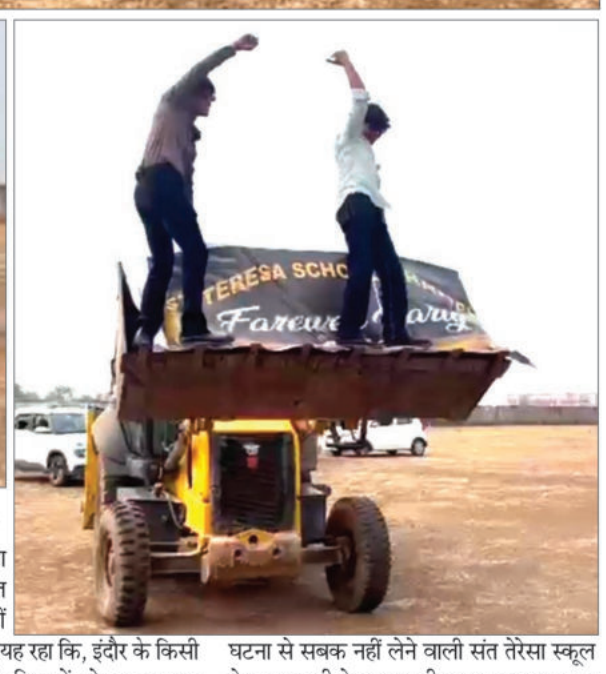

माही की गूंज, खवासा।
सुनील सोलंकी

प्रतिवर्ष स्कूलों में परीक्षाओं के पूर्व बच्चों की फेयरवेल पार्टी विदाई समारोह का आयोजन रखा जाता है। जिसमें स्कूल के अंतिम कक्षा के विद्यार्थियों को उससे छोटी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल व्यवस्थाओं के साथ यह आयोजन किया जाता है। उक्त आयोजन का उद्देश्य यह की बच्चों पर परीक्षा के चलते पढ़ाई का दबाव को कम करने तथा उक्त आयोजन के साथ बच्चों में आपसी स्नेह, उत्साह व जोश बच्चों में पढ़ाई के प्रति रहे। उक्त आयोजन पूर्ण रूप से स्कूल के मापदंडों व स्कूल प्रशासन के अधीन ही पूरी रूपरेखा बनाकर उक्त आयोजन किया जाता है। लेकिन अब देखने में आता है कि, जो यह आयोजन स्कूल के अधीन ही होते हैं लेकिन बच्चों द्वारा ऐसे खतरनाक स्टंट किए जाते हैं जिसे स्कूल प्रशासन एक श्रेय से नजर अंदाज करती है। और जब मामला सुर्खियों में आ जाता है तो स्कूल प्रशासन एक सिरे से अपनी गलती से मुकर जाता है। तथा गलती विद्यार्थियों व उनके पालकों पर मढ़ दी जाती है। जिसे किसी भी स्थिति में सही नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जब स्कूल का कोई भी विद्यार्थी खेलकूद या शिक्षा आदि किसी भी क्षेत्र में जब कोई उपलब्धि हासिल करता है तो उस सफलता का श्रेय वही स्कूल लेती है जिस स्कूल में विद्यार्थी अध्यनरत रहते हैं।

ऐसे में स्कूल के माध्यम से किसी भी प्रकार की गतिविधि होती है तो उसमें किसी विद्यार्थी द्वारा कोई गलती की जाती है तो उस गलती का जवाबदार भी स्कूल प्रशासन ही रहता है। लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा ही आयोजित आयोजन में विद्यार्थियों द्वारा गलती किए जाने पर पूरी गलती बच्चों एवं उनके पालकों पर मढ दी जाती है और जवाबदार अपना पल्ला झाड़ लेते है। वही पुलिस व विभागीय अधिकारी भी स्कूल की गलतियों को नकार देते हैं जो चिंतनिय है...!

मामला खवासा में फेयरवेल पार्टी (विदाई समारोह) का है। शनिवार को संत तेरेसा स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई समारोह के तहत फेयरवेल पार्टी का आयोजन रखा गया। स्कूल में कई गतिविधि इस आयोजन में की गई तथा स्कूल में ही सामूहिक भोजन भी रखा गया। वहीं स्कूल प्रशासन की जानकारी में आयोजित उक्त आयोजन में वाहन जुलूस निकाला गया। जिसमें बैकोलोडर (जेसीबी) मशीन भी शामिल थी। सबसे पहली गलती यह कि, यह वाहन जुलूस बाजना मार्ग स्थित संत तेरेसा स्कूल से जुलूस तेज ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे के साथ निकाला। जबकि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे को प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार जिला प्रशासन ने प्रतिबंधित कर रखा है। प्रतिबंधित डीजे के साथ संत तेरेसा स्कूल से निकला यह वाहन जुलूस ग्राम में मुख्य मार्ग से खेल स्टेडियम बामनिया मार्ग पर पहुंचा। तथा खेल मैदान से पुनः स्कूल पहुचा। खेल स्टेडियम पर व स्कूल परिसर में चलती कारों में बच्चों ने जानलेवा खतरनाक स्टंट किया। बच्चों ने कार के फाटक पर बैठ, फाटक खोल व कार में बाहर निकल कर स्टंट किया। वहीं बच्चे यहां तक भी नहीं रुके और बैकोलोडर (जेसीबी) मशीन के लोडर पर नाचते हुए खतरनाक स्टंट किया। जो कि जरा सी लापरवाही भी जनहानी को बुलावा दे रही थी।

फ़ोटो शेसन के चक्कर मे पुलिस ने परीक्षा के पूर्व बच्चों पर डाला अतिरिक्त दबाव

स्कूल प्रशासन की लापरवाही, खामियाजा भुगतना पड़ा स्कूली बच्चों और परिजनों को

पुलिसिया कार्रवाई से स्कूल प्रशासन आखिर क्यों रहा वंचित

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

पुलिस ने की चालानी कार्रवाई

पिछले वर्ष सफलता स्कूल के बच्चो ने किया स्टंट जिसका प्रमुखता से माही की गूंज में 20/02/2025 को प्रकाशित समाचार के बाद भी संत तेरेसा स्कूल ने नही लिया कोई सबक।

फेयरवेल पार्टी पर स्कूल में सिकती बाटियाँ।

पेटलावद सफलता स्कूल की घटना के बाद भी सबक नहीं लेना बड़ा अपराध

खवासा संत तेरेसा स्कूल की बात करें तो यह संस्था सेवा के नाम पर संचालित हो रही है। लेकिन असल में यह संस्था स्वार्थ और मनमानी का एक अड्डा कहा जा सकता है। यह संस्था किसी भी घटना के बाद कोई सबक लेती नहीं दिखाई पड़ती है,जिसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं।

पहला, इस संस्था की नीव ही खवासा में चार सौ बीसी के साथ रखी गई थी। यानी कि सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी को परमिशन हेतु लिखे गए प्रतिवेदन की प्रति को परमिशन बताकर स्कूल शुरू की गई।

दूसरा, खवासा में उक्त स्कूल की बस बच्चों को ला रही थी और भूत्याखाल के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। गनीमत यह रही कि, बच्चे बाल-बाल बच गए। लेकिन तात्कालिक स्कूल प्राचार्य ने जवाब में कहा कि, दुर्घटना हो गई तो हम क्या करें? यह तो हो जाती है ओर अपनी जवाबदेही से मुकर गई। इस दुर्घटना में सबसे बड़ी बात यह सामने आई थी कि, दुर्घटनाग्रस्त बस के कोई दस्तावेज ही नहीं थे। जिसके चलते यहां भी अपनी चतुराई का प्रयोग कर व पुलिस से साठ-गाठ कर पुलिस चौकी में बस तो दुर्घटनाग्रस्त बीना दस्तावेज वाली रखी। लेकिन कागजों में अन्य बस जिसके दस्तावेज थे जब्ती में बताया गया। और न्यायालय से कागजों में जप्ती बस की जमानत कराकर चौकी से बिना दस्तावेज वाली बस को सुपुर्दगी में लिया गया।

तीसरा, जबलपुर में तात्कालिक कलेक्टर द्वारा निजी स्कूलों में किताबें बिक्री पर बड़ी कमीशन खोरी का मामला उजागर किया था और जिसका असर पूरे प्रदेश में हुआ था लेकिन यह असर संत तेरेसा स्कूल में नहीं दिखाई दिया। नतीजन यह रहा कि, इंदौर के किसी गौरव बुक सेलर से किताबें लेकर खवासा व्यापारी को दी जाती रही थी। उक्त किताबें 50 प्रतिशत तक कमीशन की किताबें क्रय की जाती थी। लेकिन स्थानीय बुक सेलर को 10 से 15 प्रतिशत ही कमीशन दिया जाता था, बाकी कमीशन स्कूल की पदाधिकारी लेते रहे। जब खुलासा माही की गूंज ने किया तो पिछले वर्ष बुक सेलर बदल दिया गया। लेकिन प्राचार्य साहिबा की कारस्तानी कमीशन खोरी की ऐसी रही कि, बुक सेलर को कहा जाता रहा कि व्यापारी को क्या कमीशन देते हो मुझे नहीं पता! मुझे मेरा कमीशन चाहिए!!

वहीं पेटलावद में पिछले वर्ष सफलता स्कूल के बच्चों द्वारा वाहन रैली निकाली एवं बैकोलोडर (जेसीबी) मशीन पर स्टंट करने का मामला सार्वजनिक हुआ। जिसमें पुलिस की भी कारस्तानी सामने आई जिसमे स्कूल प्रशासन को बैगुनाह बताया और वाहन मालिकों को बुलाकर 5 से 10 हजार के चालान काटे। साथ ही पालकों को बच्चों द्वारा की गई गलती का गुनेहगार मान पालकगणो को माला पहनाकर गांधीगिरी बताने का प्रयास कर शर्मिंदा किया गया। तथा वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया। माही की गूंज ने 20 फरवरी 2025 को प्रमुखता के साथ समाचार भी प्रकाशित किया था। लेकिन किसी भी घटना से सबक नहीं लेने वाली संत तेरेसा स्कूल ने इस बार भी पेटलावद की उक्त सफलता स्कूल की घटना से भी सबक नहीं लिया। नतीजन वो सब कुछ खतरनाक स्टंट किए। जो सफलता स्कूल में देखने को मिले थे। ऐसे में क्षेत्र में यही कहा जा रहा है कि, जो स्कूली संस्था किसी घटना के बाद भी सबक लेकर सुधार नहीं कर सकती ऐसी संस्था के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए।

मामले में स्कूल प्राचार्य का पक्ष जाना तो प्राचार्य ने कहा, हम बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं, बच्चों के उक्त स्टंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम पर द्वेषभावपूर्ण भावनाएं रखी जा रही है।

प्राचार्य का उक्त जवाब अपनी जवाबदेही से विमुक्त होते नजर आ रही है। और अपनी व अपने स्कूल की पूरी गलती को बच्चों व पालको पर मढ बचने का प्रयास कर रहे हैं। पर स्कूल के जवाबदार ये भूल रहे है कि, जो वीडियो बच्चो के खतरनाक स्टंट के वायरल हो रहे है उसमें 25 सेकंड का एक वीडियो है उसमें बाटिया सिक रही है व स्कूल परिसर में ही स्कूल की बसे खड़ी है उसके आगे बीच मे बैको लोडर(जेसीबी) मशीन व डीजे है और गोल राउंड में कारे चक्कर लगा रही है और उन कार पर बच्चे स्कूल परिसर के अंदर भी स्टंट कर रहे है जो स्कूल की पूरी गलती को दर्शाता है। ऐसे में स्कूल अपनी गलतियो से मुकर नही सकता है।

वहीं पुलिस व प्रशासन भी अब तक कोई सख्त कार्रवाई इस और करते नजर नहीं आ रही है। जांच का कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। देखना है प्रशासन, स्कूल के जवाबदारो व स्कूल के विरुद्ध कोई कार्रवाई करती है या फिर बड़ी घटना के बाद ही प्रशासन अपनी ताल बजाता है की कहावत चरितार्थ होती है।

स्कूल परिसर के अंदर डीजे के साथ कार पर स्टंट करते गोल घेरे में स्कूली बच्चे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422